CARNEGIE INDIA

WORKING PAPER

दिसंबर २०२१

# चीन की भारत नीति का एक ऐतिहासिक मूल्यांकन: भारत-चीन संबंधों के लिए सबक

विजय गोखले

# चीन की भारत नीति का एक ऐतिहासिक मूल्यांकन: भारत-चीन संबंधों के लिए सबक

विजय गोखले

इस वर्किंग पेपर का हिंदी में अनुवाद धीरज कुमार ने किया है।

© 2021 Carnegie Endowment for International Peace. All rights reserved.

Carnegie does not take institutional positions on public policy issues; the views represented herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of Carnegie, its staff, or its trustees.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission in writing from Carnegie India or the Carnegie Endowment for International Peace. Please direct inquiries to:

Carnegie Endowment for International Peace
Publications Department
1779 Massachusetts Avenue NW Washington, D.C. 20036
P: + 1 202 483 7600
F: + 1 202 483 1840
CarnegieEndowment.org

Carnegie India
Unit C-5 & C-6, Edenpark,
Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi - 110016, India
P: + 011 4008687
CarnegieIndia.org

This publication can be downloaded at no cost at CarnegieIndia.org.

# विषय सूची


| | |
|---|---|
| सारांश | 1 |
| प्रस्तावना | 3 |
| कार्यविधि | 3 |
| चीन की भारत नीति, 1949–1965 | 4 |
| चीन की भारत नीति, 1965–1988 | 8 |
| शीत युद्ध के बाद चीन की भारत नीति | 12 |
| चीन की भारत नीति का आकलन और भारत के लिए रणनीतिक सुझाव | 17 |
| नीतिगत सुझाव | 19 |
| निष्कर्ष | 20 |
| लेखक का परिचय | 21 |
| नोट्स | 22 |

# सारांश

2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने भारत-चीन संबंधों के समीकरणों को बुनियादी रूप से बदल दिया। 2008-2009 के बाद से चीन की तरफ से बार-बार होने वाली घुसपैठों और सीमावर्ती क्षेत्रों में धमकाने की कोशिशों ने सीमा के सवाल को भारत-चीन संबंधों के केंद्र में ला दिया है।

इस सवाल की प्रमुखता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि 2020 में चीन की कार्रवाइयों के लिए भू-राजनीतिक प्रतिक्रिया पिछली घटनाओं की तुलना में ज़्यादा रही है, और क्योंकि भारत के नीति निर्माता और रणनीतिक समुदाय अब बीजिंग को उसके इरादों और कार्रवाइयों को लेकर संदेह का लाभ देने को तैयार नहीं हैं। इसने संबंधों के अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर भारत में व्यापक पुनर्विचार को प्रेरित किया है। जहां इस अभ्यास का ज़्यादातर हिस्सा भारतीय नज़रिए से चीन के साथ संबंध और भारत की चीन नीति को समझने की कोशिश पर रहा है, वहीं रिश्तों पर जमी मौजूदा बर्फ ने चीन की भारत नीति को समझने की ज़रूरत को रेखांकित किया है। इसलिए, चीनी स्रोतों का इस्तेमाल करके, इस शोध पत्र में चीन की भारत-नीति के प्रेरक-तत्वों का और भारतीय नीति-निर्माताओं के उस नीति से जुड़ने, उसके अनुकूल होने, और उसे ढालने के मौजूदा विकल्पों का विश्लेषण किया गया है।

इस शोध पत्र का तर्क है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष पर माओत्से तुंग के उत्थान और 1949 में चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना से ही, चीन की भारत नीति को आकार दिया है चीन, सोवियत संघ (बाद में रूस), और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्तियों के रणनीतिक त्रिकोण पर उसके दृष्टिकोण ने। जैसे-जैसे यह त्रिकोण विकसित होता गया, इसका सीधा असर भारत-चीन संबंधों पर पड़ता रहा। पिछले सत्तर सालों में ज़्यादातर वक़्त, चीन इस त्रिकोण का सबसे कमज़ोर कोना था और इसलिए सुरक्षा और हैसियत के लक्ष्यों से प्रेरित था। उस संदर्भ में, इसने भारत को सुरक्षा और हैसियत के लिए एक प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखा, जो एशिया में एक और बड़ा, विकासशील देश था। नतीजतन, चीन ने हमेशा भारत को सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसके अपने रिश्तों के चश्मे से देखा। इसने भारत को इसकी अपनी खूबियों पर नहीं देखा, या इसके दर्जे को स्वीकार किया, बल्कि इसे गैर-बराबर और गैर-भरोसेमंद माना। शीत युद्ध के दौरान चीन का उद्देश्य भारत को यथासंभव तटस्थ रखना था। शीत युद्ध के बाद की अवधि में, यह उद्देश्य हो गया चीन के आधिपत्य के रणनीतिक लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकने की भारत की क्षमता को घेराबंदी और धमकी के ज़रिए सीमित करना।

इस पत्र में तीन चरणों में चीन की भारत नीति का विश्लेषण किया गया है। 1949 से 1962 के पहले चरण में, चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने मुख्य विरोधी के तौर पर देखा और इसका मूल उद्देश्य था चीन की चिंताएं बढ़ाने वाले मामलों पर भारत को तटस्थ और अमेरिकी खेमे से दूर रखना। इसी से दूसरा उद्देश्य निकला था और वह था विकासशील देशों में भारत के प्रभाव का इस्तेमाल करके एशिया में अमेरिकी प्रवेश को रोकने के लिए "एशियाई एकजुटता" बनाना।

1962 से 1989 के दूसरे चरण में, चीन-सोवियत संबंधों में दरार और सोवियत संघ के साथ भारत के गहराते रिश्तों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चीन की चिंताएं बढ़ा दीं। इसलिए, इसकी नीति भारत को उस महाशक्ति से अलग करने की बनी रही, जो उस वक्त सोवियत संघ था। इसकी नीति भारत पर नियंत्रण रखने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की भी थी।

1991 में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध के खत्म होने के बाद, तीसरा चरण शुरू हुआ – जिसमें चीन की ये चिंताएं हावी थीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन समेत बाकी कम्युनिस्ट देशों में सत्ता परिवर्तन चाहता है। चीन अपनी परिधि को भी सुरक्षित करना चाहता था। इसलिए, इसकी नीति एक बार फिर अपनी सुरक्षा के जोखिम को घटाना था और इसके लिए ज़रूरी था कि भारत गुटनिरपेक्ष रहे और चीन की परिधि पर भारत का खतरा कम रहे। 2000 के दशक के मध्य तक, अमेरिका-चीन रिश्तों के सामान्य होने और रूस के साथ इसकी भागीदारी का मतलब था चीन के लिए अनुकूल शक्ति संतुलन, और इसके परिणामस्वरूप भारत-चीन रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा।

2013 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद, बीजिंग की विश्व मंचों पर मुखरता बढ़ने लगी है, अमेरिका के साथ चीन के संबंधों में गिरावट आने लगी है, और इसके नतीजे में भारत-चीन संबंधों में तनाव काफी बढ़ गया है। बीजिंग की भारत नीति प्रतिरोध बनाने के लिए सीमा पर निचले स्तर की धमकी भरी कार्रवाई करने की रही है। शोध पत्र का आखिरी हिस्सा इस बात की पड़ताल करता है कि क्या बदली हुई भू-राजनीतिक परिस्थितियों में चीन की यह रणनीति काम करेगी।

इस पत्र में कहा गया है कि 2020 में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर की घटनाओं ने भारत में रणनीतिक स्पष्टता ला दी है, और चीन को अपनी इस धारणा पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है कि इसकी सैन्य धमकियों का जवाब भारत की तरफ से हमेशा ही कमज़ोरी भरा रहेगा। पत्र में भारत के लिए चीन की नीति को ढालने की कोशिश करने के विकल्पों की भी चर्चा की गई है। इसमें सुझाव दिया गया है कि भारत को अपने राजनीतिक संदेशों के संकेत देने में ज़्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय होना चाहिए, कि तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए उसे एक ऊंचे राजनीतिक-रणनीतिक स्तर पर जोखिम प्रबंधन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और कि भारत-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में संबंधित हितों और चिंताओं पर चर्चा के लिए उसे एक साझा आधार ढूंढ़ना चाहिए, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

## प्रस्तावना

साल 2020 भारत-चीन संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने एक-दूसरे के प्रति दोनों देशों के बीच संबंधों के समीकरणों में मौलिक बदलाव ला दिया। 2008-2009 के बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के धमकाने वाले बर्ताव के बढ़ते जाने से सीमा विवाद एक बार फिर से रिश्तों में सबसे ऊपर आ गया है। इसकी हरकतें ग्रे-ज़ोन में होने वाली कार्रवाइयों जैसी हैं, जहां सेना की क्षमता से कम क्षमता वाली सैन्य कार्रवाई की रणनीति अपनाई जाती है लेकिन फिर भी यह भारत के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है।[1] चीन पहले भी ऐसी रणनीति का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन इस बार भू-राजनीतिक प्रतिक्रिया इसके पूर्वानुमान से कहीं ज़्यादा है क्योंकि भारत ने चीन के खिलाफ सैन्य रुख और गठजोड़ के माध्यम से संतुलन बनाने का फैसला किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में रणनीतिक और बौद्धिक बहस चीन को उसकी नीयत के मामले में संदेह का लाभ देने से हट चुकी है और अब संबंधों की नए सिरे से समीक्षा पर ज़ोर दिया जा रहा है।

भारत-चीन संबंधों का ज़्यादातर अध्ययन भारतीय दृष्टिकोण से किया जाता रहा है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य चीन की भारत नीति का विश्लेषण करना है- 1949 से लेकर अब तक इस पर किन पक्षों का असर रहा और भविष्य के संबंधों पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। चीनी स्रोतों के अभाव में इस तरह का विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण है। चीन एक बंद समाज है जहां नीति निर्माताओं की ओर से प्रत्यक्ष जानकारी को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है, और समय-समय पर अप्रिय हिस्सों की काट-छांट के बाद सिर्फ साफ-सुथरी जानकारी दी जाती है। ऐसे स्रोतों की व्याख्या करने में बड़ा जोखिम है क्योंकि मीडिया या सार्वजनिक बहसों के माध्यम से उनकी पुष्टि कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी विश्लेषण पक्षपाती हो सकता है, लेकिन इन दो प्रमुख एशियाई देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर काम कर रहे नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए फिर भी यह विश्लेषण काम का हो सकता है।

## कार्यविधि

इस पत्र में तीन तरह के प्राथमिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हुए चीनी नेताओं के भाषण हैं। ये भाषण आम तौर पर छोटे अंश या सारांश होते हैं, लेकिन ये चीन के शीर्ष नेतृत्व की सोच की सीधी और गहरी जानकारी देते हैं, और ये चीनी लोगों को संदेश देने का एक माध्यम भी हैं। दूसरी तरह की प्राथमिक लिखित सामग्री में चीनी राजनयिकों, विशेषकर स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्रियों के संस्मरण शामिल हैं। यह माना जा सकता है कि ऐसे लेखन को प्रकाशित किए जाने से पहले काफी सावधानी से जांचा गया होगा, लेकिन इसके बावजूद उनसे चीन के विदेश नीति संस्थान के प्रमुख अधिकारियों की बनाई जाने वाली नीति के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे तरह की प्राथमिक सामग्री में ऐसे लेख शामिल हैं जिन्हें चीनी विशेषज्ञों के दल (थिंक टैंक) ने प्रकाशित किया है।

इस शोध पत्र का फोकस भारत-चीन संबंधों से जुड़ी किन्हीं खास घटनाओं या विवादों पर नहीं है। इसका उद्देश्य इस बात का विश्लेषण करना है कि चीन की भारत नीति का ढांचा क्या रहा है और मौजूदा संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता क्या है। पहले तीन भागों में उन कारणों का विश्लेषण किया गया है जिन्होंने 1962 के पहले, 1962 से शीत युद्ध खत्म होने तक और शीत युद्ध के बाद की अवधि में चीन की भारत नीति को आकार दिया। अंतिम भाग में इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई है कि गलवान घटना के बाद के संदर्भ में नीतियों के क्या असर दिखे हैं और चीन की नीति को पारस्परिक रूप से संतोषजनक मार्ग पर ले जाने के लिए भारत क्या कर सकता है।

इस शोध पत्र में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद से इसकी भारत नीति को चीन, सोवियत संघ (बाद में रूस) और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्तियों के रणनीतिक त्रिकोण के बड़े ढांचे के अंदर आकार दिया गया है। पिछले सत्तर सालों में चीन इस त्रिकोण का सबसे कमज़ोर बिंदु था और इसलिए सुरक्षा की चिंताओं और कमज़ोर हैसियत से प्रभावित था। इस

रणनीतिक त्रिकोण के संदर्भ में चीन भारत को एक सुरक्षा समस्या के तौर पर देखने के साथ-साथ हैसियत के लिए एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में, और द्विपक्षीय स्तर पर इसके अपने दम पर नहीं बल्कि दूसरी महाशक्तियों के एक सहायक के रूप में देखता था। इसलिए बीजिंग के दृष्टिकोण से रिश्ता बराबरी का नहीं था। शीत युद्ध के दौरान जब चीन आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका उद्देश्य भारत को, जिस पर वो भरोसा नहीं करता था, यथासंभव तटस्थ रखना था, और, फिर शीत युद्ध के बाद की अवधि में चीन का उद्देश्य अपने आधिपत्य के रणनीतिक लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने की भारत की क्षमता को नियंत्रण और सैन्य कार्रवाई के ज़रिए रोकना था।

चीन को ऐसा भी लगता था कि भारत की राजनीतिक प्रणाली और दोनों देशों की आर्थिक ताक़त में गैर-बराबरी की वजह से उसे अपनी भारत नीति को इस तरह नया आकार देने की ज़रूरत नहीं है जिसमें भारत के हितों को भी सार्थक रूप से शामिल किया जाए। इसलिए, ऐसा लगता है जैसे इसकी सैन्य कार्रवाइयां भारत पर चीनी रणनीतिक चिंताओं को दूर करने का दबाव डालने के इरादे से की जा रही हों, साथ ही चीन भारत को कहता है कि वो अपनी चिंताओं को स्थानीय परेशानियों के तौर पर संभाले और उन्हें इस तरह से ना उठाए कि दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ें। चूंकि चीन के नेता भारत के साथ रणनीतिक की अपेक्षा सामरिक रूप से ज़्यादा व्यवहार करते हैं, वे समय-समय पर अपनी बात मनवाने के लिए सैन्य कार्रवाइयों का सहारा लेते रहे हैं। ऐसा लगता है उन्होंने मान लिया है कि भारत के पास चीन पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए हिम्मत, काबिलियत या ताक़त बेहद कम है।

इस शोध पत्र का तर्क है कि 2020 के बाद कई वजहों से परिस्थिति में बदलाव आया होगा, जिसमें भारत द्वारा चीन का पुनर्मूल्यांकन, पहले से बड़ी राजनीतिक इच्छाशक्ति और साथ-साथ चीनी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने के लिए बेहतर सैन्य तैयारियां शामिल हैं। नतीजतन हो सकता है कि चीन ने दोनों देशों के बीच ताक़त के अंतर को ज़्यादा आंक लिया हो और भारत की भू-राजनीतिक प्रतिक्रिया की क्षमताओं को कम करके देखने की गलत कूटनीतिक गणना कर ली हो। तनाव का बढ़ना और संवाद का अभाव जोखिम-प्रबंधन को और मुश्किल बना देगा और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं वाली बड़ी शक्ति के रूप में चीन को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शोध पत्र का निष्कर्ष यह है कि चीन को, भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखते हुए उसके प्रति अपनी नीति में बदलाव लाना चाहिए, इसके साथ-साथ उसे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संदर्भ में एक कार्यप्रणाली विकसित करने की ज़रूरत है। क्या भारत चीन के रणनीतिक दृष्टिकोण को बदल सकता है और कैसे? और क्या चीन महामारी के बाद तेज़ी से बदलती वैश्विक और क्षेत्रीय दुनिया में अपनी भारत नीति को फिर से गढ़ेगा? यही तथ्य इसका फैसला करेंगे कि दोनों देश विवेकपूर्ण तरीके से अपनी प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करेंगे या संघर्ष में फंसे रहेंगे।[2]

## चीन की भारत नीति, 1949–1965

1949 से पहले विदेश नीति को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी मुख्य चिंता थी संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया और उसके साथ संबंध। शुरुआत में पार्टी को लगता था कि वॉशिंगटन समझौते के खिलाफ नहीं था, लेकिन 1946 के अंत तक यह भ्रम टूट गया। झाऊ एनलाई की शिकायत थी कि अमेरिकी दूत धोखेबाज थे।[7] माओ और झाऊ ने अमेरिकियों को साम्राज्यवादी करार दिया और सोवियत संघ के नेतृत्व में एक साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चे की बात की।[8] 1949 में, झाऊ ने मांग उठाई कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन से अपने पूरे सैन्य बल को वापस बुलाए, यह कहते हुए कि "हमें उनका सफाया करने का अधिकार है।"[9] उस समय से, संयुक्त राज्य अमेरिका को अस्तित्व के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा। माओ ने सोवियत संघ के पक्ष में झुकने और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक मोर्चा बनाने के फैसले की घोषणा की।[10]

इस प्रकार, जब अक्टूबर 1949 में चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दो मुख्य विचार थे: पहला कि क्षेत्र में चीन बिना किसी समकक्ष के प्रमुख एशियाई ताकत था और दूसरा कि संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य शत्रु था। चूंकि, पार्टी और राज्य पूरी तरह से एक ही थे, इसलिए नए शासन के ढांचे में ये दोनों विचार पूरी तरह जड़ जमाए हुए थे।

इस चीनी विश्व दृष्टिकोण में भारत की जगह कहां थी? जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, और माओ 1930 के दशक में आपस में पत्राचार किया करते थे।[11] अगस्त 1939 में, नेहरू चीन के शहर चोंगक़िंग गए और माओ के सहयोगियों से मिले। 1942 की शुरुआत में, तत्कालीन राष्ट्रपति च्यांग काई शेक भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन दिखा रहे थे।[12] वैश्विक मामलों में रुचि होने के कारण माओ को अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के बारे में पता रहा होगा, लेकिन 1945 के पहले माओ और झाऊ में से किसी ने भी अपने लेखों में इसका ज़िक्र नहीं किया। यहां तक कि जितने एशियाई और अफ़्रीकी उपनिवेश भारत के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे थे, उतने चीन का नहीं। उन्होंने उपनिवेशों में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम का सिर्फ सामान्य उल्लेख किया।[13] 1936 में अमेरिकी पत्रकार एडगर स्नो को माओ के दिए एक साक्षात्कार से तो ऐसा लगता है कि वो एशिया को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने की लड़ाई में भारत के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। माओ ने स्नो से कहा कि, "जब चीनी क्रांति पूरी ताकत से आएगी, तब कई औपनिवेशक देशों की जनता चीन के उदाहरण का अनुसरण करेगी।"[14] चीनी नेता युद्ध के बाद के "एफ्रो-एशिया" में चीनी क्रांति को "सबसे महत्वपूर्ण घटना" मानते थे।"[15] चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की रणनीतिक सोच में यह कल्पना हावी थी कि चीन तीसरी दुनिया और साम्यवादी आंदोलन का केंद्र है।

1954 में, माओ ने दूसरे विश्व युद्ध के लाभार्थियों को तीन वर्गों में बांटा: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन जैसे देश जिनका नेतृत्व साम्यवादी या समाजवादी दल कर रहे थे, और भारत जैसे "उत्पीड़ित राष्ट्र" जिनका नेतृत्व साम्यवादी दल नहीं बल्कि "देशभक्त संगठन" कर रहे थे।[16] इससे पता चलता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भारत एक निम्न श्रेणी में आता था, शायद इसलिए क्योंकि इसकी क्रांति अधूरी थी। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रमुख साम्राज्यवाद-विरोधी ताकत थी, 1943 में माओ ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया और उसे "जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे साथ"[17] बताया। माओ को उम्मीद थी कि भारत की आज़ादी के बाद वहां उनके जैसी सोच वाली समाजवादी सरकार की शुरुआत हो सकती है।

इस तथ्य के अलावा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एशिया में भारत की भूमिका को अपनी तरह महत्वपूर्ण नहीं समझती थी और उसे बराबरी से नहीं देखती थी, अवर्गीकृत दस्तावेज़ों से यह भी पता चलता है कि शुरुआत से ही चीनी उच्चाधिकारियों में भारत को लेकर गहरा अविश्वास था। नेहरू को लेकर माओ का दृष्टिकोण नकारात्मक था। 19 नवंबर, 1949, को उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, भालचंद्र त्र्यंबक रणदिवे को लिखी चिट्ठी में नेहरू को साम्राज्यवाद का "सहयोगी" बताया।[18] युद्ध के बाद के राजनीतिक हालातों में दोनों बड़े गुटों के प्रति भारत के तटस्थ रुख के कारण, उसे दूसरे पक्ष के समर्थक के तौर पर देखने का सीसीपी का नज़रिया शायद और गहरा गया होगा। नेहरू एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहते थे। लेकिन, भले ही नेहरू ने कहा था कि "हम चीन के खिलाफ दिखने वाली किसी भी गतिविधि के साथ खड़े होने का इरादा नहीं रखते,"[19] माओ का मानना था कि हर व्यक्ति को "साम्राज्यवाद या समाजवाद में से किसी एक की तरफ झुकना होगा।" तटस्थ रहने से काम नहीं चलेगा, और न ही कोई तीसरा रास्ता है।"[20] चीन की नज़रों में, भारत समाजवादी गुट का हिस्सा नहीं था और इसलिए साम्राज्यवादी गुट का हिस्सा था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने नेहरू को "अमेरिकी साम्राज्यवाद का पूरा वफ़ादार नौकर" और "अमेरिकी अनुचर" कहा था जिसे अपने अमेरिकी "मालिकों" से एशिया में नेतृत्व की बड़ी भूमिका चाहिए थी।"[21] चीन के नए नेताओं ने भारत में साम्यवादी अधिग्रहण के लिए सोवियत संघ के साथ साज़िश रची। दिसंबर 1950 में, चीनी नेता लिउ शओची और झाऊ एनलाई,"अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद के विनाश में भारत को जो भूमिका निभानी चाहिए उस संबंध में", सोवियत संघ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मज़बूत करने का आग्रह कर रहे थे।[22]

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चीन के दिमाग में युद्ध के बाद के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत के लिए एक स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में कोई जगह नहीं थी क्योंकि न तो भारत चीन के बराबर था और न ही वैचारिक रूप से उसके जैसा। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी-पूंजीवादी शिविर के हिस्से के तौर पर माना जाता था। निहितार्थ यह है कि भारत की खुद की कोई हस्ती नहीं थी जो स्वतंत्र रूप से काम करे और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब यह नहीं था कि शुरुआती सालों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भारत का कोई उपयोग नहीं था। इसने "संयुक्त मोर्चा" रणनीति अपनाकर अमेरिकी चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया था।[23] झाऊ के अनुसार, रणनीति थी, "शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय बलों (मतलब समाजवादी देशों) की ताकत को एकजुट करना और उन्हें मज़बूत करना और पूर्व औपनिवेशिक और अर्ध औपनिवेशिक राज्यों के साथ (मिलकर) और उन्हें जीतकर नए चीन के प्रभाव को बढ़ाना।" दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को

लेकर उनकी सोच और भी ज्यादा स्पष्ट थी: उन्होंने कहा, "हमें उन्हें जीतने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो युद्ध के समय तटस्थ रहें और शांति के समय साम्राज्यवादियों से दूरी बनाए रखें।"[24] दूसरे शब्दों में, रणनीति यह थी कि "एशियाई एकजुटता" का निर्माण करके चीन के आस-पास के क्षेत्र में नए स्वतंत्र हुए देशों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई जगह न दी जाए। इसमें एशियाई सरकारों को इस बात पर राज़ी करना शामिल था कि तटस्थ रहना और युद्ध के बाद के एशिया के निर्माण में चीन की मदद करना एशियाइयों के हित में सबसे अच्छा है। इस नीति को लागू करने के लिए भारत को मनाना एक मुख्य लक्ष्य था।

इस प्रकार, चीन की भारत नीति के मूल में दो मुख्य सूत्र शामिल थे। पहला, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे का अनुयायी बनने से रोकना, और चीन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसे तटस्थ रखने की नीति बनाना। दूसरा, विकासशील दुनिया में भारत की स्थिति और प्रभाव का इस्तेमाल "एशियाई एकजुटता" के निर्माण में किया जाना ताकि एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की घुसपैठ को रोका जा सके।

भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर रखना चीन की नीति का मुख्य उद्देश्य बन गया था।[25] इस उद्देश्य के लिए मनाने के अलावा दबाव का इस्तेमाल किया गया। अगस्त 1949 में, एक वरिष्ठ चीनी राजनयिक, हैन नियानलॉन्ग ने राष्ट्रवादी सरकार में भारत के राजदूत के एम पन्निकर से कहा कि "एक ही चीज़ है जो ऐसे (भारत-चीन) संबंधों के विकास को रोक सकती है और वो है भारत का अमेरिकी गतिविधियों के लिए खुद को इस्तेमाल होने देना।"[26] 1952 में, झाऊ ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर "इस (भारत-चीन) दोस्ती को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया।" [27] 1954 में, माओ ने दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका "मौका मिलते ही हमें नुकसान पहुंचाने को तैयार रहता है," और संकेत दिया कि यह भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा।"[28] सीसीपी ने "एशिया की आज़ादी के खिलाफ अमेरिकी साजिश,"[29] की बात करके या 1954 में माओ की तरह यह दावा करके, कि "हम, पूर्व के लोगों" को साम्राज्यवाद से निपटना होगा और एक-दूसरे की रक्षा करनी होगी, भारत के नेताओं पर दबाव बनाया।[30] भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग रखने के लिए चीन ने हमेशा साम्राज्यवाद बनाम नए स्वतंत्र राज्यों और एशियाई लोगों द्वारा स्वयं अपने भाग्य के निर्धारण के संदर्भ में मुद्दे तैयार किए। दूसरे शब्दों में, ऐसा खाका खींचा जिससे भारत जुड़ाव महसूस कर सके।[31] 1950 के दशक के मध्य तक, नेहरू बीजिंग में अपने राजदूत से कहते थे कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में चीन के ज़्यादा क़रीब है।[32] भारत ने सीसीपी की ओर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वकालत शुरू कर दी। अक्टूबर 1954 में, नेहरू ने दावा किया कि इसमें "कोई शक नहीं है कि चीन की सरकार और लोग शांति चाहते हैं"।[33] यहां तक कि 1956 के राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भारत ने चीन के पक्ष में तर्क देकर यह दावा किया कि "ऐसा नहीं लगता कि वह किसी दूसरे देश के खिलाफ आक्रामक नीयत रखेगा", और उन्होंने चीन के प्रति अमेरिका की दुश्मनी को उस समय की मुख्य समस्या बताया।[34]

चीन की भारत नीति का दूसरा उद्देश्य अपने आस-पास और परिधीय क्षेत्रों में तटस्थ एशियाई देशों की एक पट्टी तैयार करना था ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी घेराबंदी ना कर सके। चीन ने, एक बार फिर, "संयुक्त मोर्चा" रणनीति का सहारा लिया। 1950 में, झाऊ ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक टी एन कौल से कहा, कि "किसी भी साम्राज्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए सभी एशियाई देशों को दोस्ती, शांति और आपसी सम्मान के आधार पर एकजुट होना चाहिए।"[35] 1954 में, वो "किसी तरह की एशियाई शांति संधि पर हस्ताक्षर की तैयारी करने और दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन (SEATO) बनाने के संयुक्त राज्य अमेरिका के षड्यंत्र को रोकने के लिए हवाई रास्ते से भारत पहुंचे।"[36] सीसीपी ने 1955 में बांडुंग में हुए एशियाई- अफ्रीकी सम्मेलन को एशियाई एकजुटता के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका विरोधी मोर्चा तैयार करने के लिए एक अच्छे मंच के तौर पर देखा।[37] इसने "शांति के संयुक्त मोर्चे के विस्तार की सामान्य रेखा" के अंतर्गत विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ देशों को "शांति और तटस्थ" से लेकर "शांति-विरोधी और तटस्थ-विरोधी," के रूप में बांटा।"[38] इस रणनीति को लागू करने के लिए भारत एक मुख्य साधन था। संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एशियाई मोर्चा बनाने का उद्देश्य पूरा करने के लिए सीसीपी ने एशियाई नेताओं के साथ मिलकर काम किया।[39] इस समय चीन की नीति का एक छिपा लक्ष्य, विशेषकर बांडुंग सम्मेलन के इर्द-गिर्द, सोवियत संघ से स्वतंत्र एक तीसरी दुनिया का क्षेत्र बनाकर चीन के लिए एजेंसी के तौर पर भारत को इस्तेमाल करना भी हो सकता है।

बांडुंग सम्मेलन चीन की शुरुआती भारत नीति का शीर्ष बिंदु था। चूंकि चीन ने भारत के साथ अपने संबंधों को महाशक्ति संबंधों के ढांचे के अंदर रूप दिया था और इसका मुख्य उद्देश्य इसे तटस्थ रखना था, यह नीति तब तक कारगर थी जब तक भारत महाशक्ति संबंधों पर चीन के दृष्टिकोण से सहमत रहा, इस बड़े परिप्रेक्ष्य में चीन की चिंताओं पर ध्यान देता रहा और अपनी समस्याओं की चर्चा नहीं की। शायद चीन चाहता था कि भारत उसके बड़े दृष्टिकोण को साझा करे और अपनी चिंताओं को स्थानीय समस्याओं के तौर पर सुलझाए, लेकिन बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ ना करे। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में, जब भारत ने द्विपक्षीय चिंताओं को खुलकर व्यक्त करना शुरू किया, चीन तब भी इन्हें सिर्फ महाशक्ति संबंधों के चश्मे से देखता था न कि द्विपक्षीय रूप से। इसने मान लिया था कि भारत, तिब्बत (जो चीन के लिए आंतरिक मुद्दा था) या सीमा विवाद (चीन के मुताबिक भारत के दावे अवैध थे) जैसी समस्यों को सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन पाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यह तर्क सीसीपी की इस वैचारिक सोच के साथ भी ठीक बैठता है कि एक बुर्जुआ शासक वर्ग के तौर पर भारत सरकार पूंजीवादी थी और उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। मार्च 1959 में तिब्बती विद्रोह और दलाई लामा के भारत पहुंचने, और उसके बाद दिसंबर 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर के आगमन पर भारत ने जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उससे इस धारणा को और बल मिल गया। झाऊ एनलाई और देंग शियाओ पिंग ने दावा किया कि भारत ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के सक्रिय समर्थन से तिब्बत में समस्या को बढ़ा रहा था।[40] उसी समय, 1955 में सोवियत नेताओं निकिता ख्रुश्चेव और निकोलाई बुल्गानिन के भारत दौरे के बाद, और खासकर अक्टूबर 1959 में बीजिंग में भारत को लेकर ख्रुश्चेव और माओ के बीच हुई तीखी बातचीत के बाद चीन को भारत-सोवियत संघ के बढ़ते संबंधों की चिंता भी सताने लगी थी।[41]

सामरिक त्रिकोण के भीतर बदलते समीकरणों ने 1958 के बाद चीन की भारत नीति को और जटिल बना दिया। ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ते अमेरिकी सैन्य बलों को सीसीपी आक्रमण की तैयारी के तौर पर देख रहा था — झाऊ ने इसकी व्याख्या "युद्ध के कगार पर आग के साथ खेल"[42] के तौर पर की। 1959 में ख्रुश्चेव के वॉशिंगटन दौरे के बाद, सीसीपी को लगा कि दो महाशक्तियां इसके खिलाफ मिलकर साज़िश कर सकती हैं।[43] इसका सबसे बड़ा डर चीन से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका-सोवियत संघ का साथ आना था, जिसमें भारत के साथ इसके अपने संबंध भी शामिल थे। त्रिकोणीय महाशक्ति संबंधों के इस बदले हुए संदर्भ में चीन ने भारत को तटस्थ रखने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया। मई 1959 के बाद दुष्प्रचार नरम पड़ गया था। माओ ने ख़ुद एक मैत्रीपूर्ण संदेश तैयार किया।[44] राजदूत पैन ज़िली ने कहा था कि "चीन इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह पूर्व में अमेरिका से दुश्मनी मोल ले और दक्षिण-पश्चिम में भारत से," और साथ ही यह भी कहा कि "हमारे पास ध्यान खींचने के दो केंद्र नहीं हो सकते, और ना ही हम मित्र (भारत) को शत्रु समझ सकते हैं। यह हमारी राज्य नीति है।"[45] सितंबर 1959 में, झाऊ ने भारतीय राजदूत को एशिया के लिए चीन-भारत मित्रता के बड़े महत्व के बारे में बताया।[46] ऐसा माना जाता है कि जनवरी 1960 में, सीसीपी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति ने सीमा के सवालों पर समझौता वार्ता के लिए दिशा-निर्देश अपनाए।[47] यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत नीति में यह सामरिक समायोजन चीन के आस-पास बिगड़ रहे सामरिक परिवेश की वजह से किया गया था।

अप्रैल 1960 में झाऊ एनलाई की दिल्ली यात्रा- जब वो माओ का संदेश लेकर आए थे कि चीन का "दुश्मन पूर्व में है और वह समुद्र के रास्ते से आएगा। हम भारत को अपना मित्र राष्ट्र मानते हैं और हम अपनी दक्षिणी सीमा को एक राष्ट्रीय मोर्चे में नहीं बदल सकते," और सीमा तय करने का प्रस्ताव[48]—असफल रही। इसने उस चीनी दृष्टिकोण की दोबारा पुष्टि की, कि चीन जिस विषम परिस्थिति का सामना कर रहा था भारत उसका फायदा उठाना चाहता था। दिल्ली में चीनी दूतावास का आकलन था कि "चीन और साम्यवाद का विरोध, अमेरिका पर निर्भरता और विदेशों में अपना विस्तार करना, भारतीय शासक मंडल की विदेश नीति के लिए दीर्घकालिक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं; इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का केंद्र बिंदु चीन के प्रति दीर्घकालिक शत्रुता है।"[49] सीसीपी ने निष्कर्ष निकाला कि सीमा पर भारत का रुख अमेरिका के साथ मिलकर चीन पर दो मोर्चों से दबाव बनाने की एक समग्र रचना का हिस्सा था।[50] माओ के एक बयान से स्पष्ट है कि चीन इन घटनाओं को सिर्फ द्विपक्षीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि त्रिकोणीय महाशक्ति संबंधों के संदर्भ में देखता था। माना जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि भारत के साथ हमारी लड़ाई एक जटिल अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है; ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही समस्या है, अमेरिका और सोवियत संघ और दूसरे देश भी भारत की मदद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुश्किल घड़ी में वे हमें बीच मैदान में खींचकर सबक सिखा सकते हैं। लेकिन हम उनके इरादों के आगे झुकेंगे नहीं।[51]

इसलिए माओ ने 1962 के सीमा युद्ध को एक राजनीतिक-सैन्य युद्ध कहा था। उन्होंने दोहरे लक्ष्य के साथ रणनीति, युद्धनीति और समय तय किया था ताकि महाशक्तियों को यह दिखा सकें कि भारत एक भरोसेमंद एशियाई साथी नहीं है और भारत को तटस्थ मुद्रा में वापस आने के लिए मजबूर किया जा सके।

सीमा युद्ध से बहुत कम हासिल हुआ। इससे भारत को तटस्थ मुद्रा में वापस नहीं लाया जा सका बल्कि इसके उलट, नेहरू ने युद्ध को "भारत और चीन के बिगड़ते संबंधों की अंतिम पराकाष्ठा"[52] कहा। भारत ने पश्चिम से सैन्य मदद मांगी। चीनियों की यह उम्मीद पूरी नहीं हुई कि भारत सीमा प्रश्न को हल करने के लिए झुक जाएगा।[53] यह चीन के साथ आने वाली बार-बार की समस्या है- उसकी धमकाने वाली नीति के हमेशा उसके दावे के विपरीत नतीजे निकलते हैं। दिसंबर 1962, मार्च 1963, और अप्रैल 1963 में झाऊ एनलाई के बातचीत दोबारा शुरू करने के प्रस्तावों के साथ-साथ उनके बयान "हमने भारत के साथ मित्रता की अपनी इच्छा छोड़ी नहीं है,"[54] पर भारत की प्रतिक्रिया ठंडी रही। संबंधों को दोबारा ठीक करने के बजाय, चीन की कार्रवाई ने सदी के चौथाई हिस्से के लिए एक गतिरोध पैदा कर दिया। अमेरिका विरोधी मोर्चे के तौर पर एशियाई एकजुटता के चीन के लक्ष्य को भारी नुकसान पहुंचा और इसकी भारत नीति ध्वस्त हो गई।

चीन की भारत नीति के पहले चरण के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले, दो अन्य सिद्धांतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला सिद्धांत, ऐसा माना जाता है कि 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' के दौरान माओ आर्थिक नीति के लिए पार्टी में जिस आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे थे उसका असर भारत के साथ संबंधों पर पड़ा होगा। इस शोध पत्र में सीमा युद्ध के तात्कालिक प्रभावों की जांच नहीं की गई है। जहां तक भारत पर चीनी हमले की संभावना और समय का संबंध है, यह संभव है कि घरेलू आर्थिक संकट और उसके साथ भारत-चीन सीमा पर बिगड़ते माहौल एक-दूसरे से जुड़े हों। फरवरी 1961 में झाऊ एनलाई को सोवियत संघ में पूर्व राजदूत वांग जियाक्सियांग के लिखे एक पत्र के बावजूद कि सीमा प्रश्न पर गतिरोध खत्म करने के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए, ऐसे प्रमाण हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि 1959 से लेकर सीमा युद्ध तक, भारत से निपटने को लेकर सीसीपी नेतृत्व के अंदर काफी हद तक सहमति थी।[55] कुल मिलाकर, चीन की भारत नीति एक सामूहिक फैसला लगती है। दूसरी तरफ, तिब्बत की वजह पर विचार करना चाहिए। शुरुआती वर्षों में यह मुद्दा निश्चित तौर पर एक द्विपक्षीय चिंता थी, लेकिन भारत के इरादों को लेकर चीन की शुरुआती गहरी चिंताएं 1954 तक सुलझ चुकी थीं। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में चीनी लेखन, जिसमें नेतृत्व के वक्तव्य शामिल हैं, आमतौर पर तिब्बत में अंग्रेज़ी-अमेरिकी प्रयासों से जुड़े हैं। भारत की भूमिका को आम तौर पर इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है।

चीन की भारत नीति के पहले चरण से तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, चीन भारत को अपने से कम बराबरी वाला, पश्चिमी विचारधारा का समर्थक और इसी वजह से भरोसेमंद नहीं मानता था। दूसरा, इसकी भारत नीति महाशक्तियों के आपसी संबंधों से तय होती थी। मुख्य उद्देश्य चीन पर रणनीतिक दबाव कम करना था और इसी हिसाब से भारत के साथ रणनीति को आकार दिया गया था। तीसरा, भारत ने 1959 के मध्य से 1960 के अंत के बीच मिला एक मौका शायद खो दिया था, जब चीन ने अपनी नीति में एक सामरिक बदलाव किया था।

## चीन की भारत नीति, 1965- 1988

1965 के बाद, चीन का पूरा ध्यान सांस्कृतिक क्रांति की ओर था, और भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1 मई 1970 को माओत्से तुंग ने बीजिंग में भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी ब्रजेश मिश्र[56] को अपनी सरकार को यह संदेश भेजने के लिए कहा: "हम ऐसे झगड़ नहीं सकते हैं। हमें अपने संबंधों को सुधारने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। भारत एक महान देश है। भारत के लोग अच्छे लोग हैं। एक दिन हम फिर दोस्त बनेंगे।"[57] माओ ने अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुना था। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने मिश्रा से कहा था कि यह टिप्पणी "दोनों देश के बीच संबंधों के मूल सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है।"[58] जुलाई में प्रधानमंत्री झाऊ एनलाई के जरिए एक और संदेश भेजा गया[59], और फिर अगस्त में उप विदेश मंत्री चाओ गुआनहुआ ने संकेत दिए कि चीन भारत की ओर से दोस्ताना प्रस्तावों को गंभीरता से लेगा।[60] किस वजह से चीन ने 1970 में भारत से संबंधों को सुधारने के लिए कदम बढ़ाए?

भारत की प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी ने, 1969 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन से संबंध सुधारने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन, माओ के प्रस्तावों के पीछे की वजह द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने की मंशा थी, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है।[61] चीन ने कभी सीधा जवाब नहीं दिया, और सार्वजनिक तौर पर चीन का भारत विरोधी रवैया कुछ और वक्त तक चलता रहा था। माओ के भारत से संपर्क करने की वजह कुछ और थी।

सोवियत संघ के साथ गठबंधन, चीन की विदेश नीति का मूल-आधार था। लेकिन, 50 के दशक के अंत तक, दोनों के रिश्तों में दरार पड़ने लग गई थी क्योंकि बीजिंग सोवियत संघ के "दिखाए गए रास्ते"[62] पर चलने के लिए राज़ी नहीं था। 1969 की शुरुआत में (डमानस्की/जेनबाओ द्वीप) सीमा पर टकराव के बाद, दोनों देश के बीच की डोर टूट गई। माओ ने ऐलान किया: "अब हमारा सामना एक विकट विरोधी से होने जा रहा है।"[63] पूर्व विदेश मंत्री तैंग जिशुआन के मुताबिक 1969 से 1979 के दौरान चीन और सोवियत संघ के बीच "अत्यधिक प्रतिरोध" था।[64] 1969 में सोवियत संघ ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा और भारत के समर्थन की अटकलों ने चीन की चिंताओं को बढ़ाया होगा कि वह हर तरफ से घिर सकता है। अगर माओ के बायोग्राफर की मानें, तो माओ ने यह कहा था:

> उत्तर और पश्चिम में सोवियत संघ, दक्षिण में भारत और पूर्व में जापान। अगर हमारे सारे विरोधियों ने हाथ मिला लिया और चारों दिशाओं से आक्रमण किया, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए?[65]

रिचर्ड निक्सन, जो 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनें, वो चीन के साथ संबंधों को सुधारना चाहते थे पर यह कोशिश एकदम शुरुआती चरण में थी। 1969 में चीन की चिंता यह थी कि भारत और अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बीच तनाव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चीनी साम्यवादी दल ने अगस्त 1969 में एक जनरल मोबिलाइजेशन ऑर्डर जारी किया जिसमें यह चिंता साफ झलकती है।[66] इसलिए 1970 में माओ के मित्रता प्रस्ताव को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। संभवत: यह भारत को सोवियत संघ की ओर झुकने से रोकने का प्रयास था क्योंकि उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चीन काफी चिंतित था।

1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की वजह से माओ के प्रस्ताव पर सार्थक ढंग से आगे नहीं बढ़ा जा सका था। तत्कालीन विदेश मंत्री हुआंग हा ने अपनी जीवनी में लिखा है कि चीन ने संबंध सुधारने की प्रक्रिया को इस वजह से निलंबित कर दिया क्योंकि "भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता समझौता करने के बाद पाकिस्तान के साथ तीसरे युद्ध का ऐलान कर दिया।"[67] दक्षिण एशिया में चल रहे इस शक्ति संघर्ष में सोवियत संघ की भागीदारी का हवाला देकर चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान चीनी अधिकारी अक्सर "सोवियत संघ को भारतीय आक्रमणकारियों का नेता"[68] कहकर पुकारते थे। माओ और झाऊ अक्सर भारत की काबिलियत पर संदेह जताने वाले बयान देते थे। 1973 में माओ ने अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर से कहा था "भारत ने आज़ादी नहीं जीती थी। अगर इसने खुद को ब्रिटेन के साथ नहीं जोड़ा तो सोवियत संघ के साथ जोड़ लिया।"[69] ऐसी टिप्पणियां दर्शाती हैं कि चीन भारत को स्वतंत्र देश के तौर पर नहीं, बल्कि, बाहुबली देशों के सहायक के रूप में देखता था। बस, संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह सोवियत संघ ने भारत के प्रमुख संरक्षक की जगह ले ली थी।

1962 में भारत नीति के पतन के बाद, चीन ने भारत को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान का उपयोग करने की रणनीति बनाई। उसका मानना था कि अमेरिका से बेहतर रिश्ते और पाकिस्तान के साथ रणनीतिक समझौते के बाद सोवियत संघ और भारत, चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के बारे में ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे। चीनी राजनेता यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत के लक्ष्य सोवियत संघ के दक्षिण एशिया के उद्देश्यों से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए वे 1971 में पाकिस्तान के विभाजन या फिर 1975 में भारत में सिक्किम के विलय को रोकने में सफल नहीं हो पाए। इस घटनाक्रम के साथ 1974 के पहले परमाणु परीक्षण ने भारत को दक्षिण एशिया के प्रमुख शक्तिशाली देश के तौर पर स्थापित कर दिया। इस तरह भारत नीति गढ़ने का माओ का दूसरा प्रयास भी विफल हो गया।

1976 में माओ और झाऊ के निधन ने नई संभावनाओं को जन्म दिया। भारत में भी आपातकाल के बाद नए राजनेताओं ने सत्ता संभाली। चीन के सर्वशक्तिमान राजनेता देंग शियाओ पिंग ने सीमा संबंधी सभी मुद्दों पर समझौते के लिए "पैकेज-डील" का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तब के विदेश मंत्री (जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने) अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि चीन पूर्वी क्षेत्र में पीछे हटने को तैयार है अगर बाकी जगहों पर भारत समझौता करने को राजी हो।[70] इस प्रस्ताव को दो बार रखा गया। पहली बार, जून 1980 में, इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में, जब विक्रांत नामक पत्रिका के संपादक, कृष्ण कुमार, ने देंग का साक्षात्कार किया। उस साक्षात्कार के दौरान देंग ने यह जताने की कोशिश की कि "चीन संबंधों को सुधारने के लिए उतना ही गंभीर था जितनी श्रीमती गांधी थीं"।[71] अक्टूबर 1982 में चीन के दौरे पर गए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल के सामने देंग ने वही इच्छा दोहराई थी।[72] हुआंग हा ने अपनी जीवनी में माना है कि भारत ने "अपनी चीन-नीति में बदलाव किए और सीमा संबंधी मुद्दों पर लचीला और व्यावहारिक रुख अपनाया ताकि दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए अनुकूल परिस्थिति बने," लेकिन, "भारत के पूर्वी क्षेत्र की मांगों पर अड़े रहने और पश्चिमी सीमा पर बेबुनियादी मांगों को पूरी तरह ना छोड़ने की वजह से पैकेज डील फॉर्मूला को लागू नहीं किया जा सका।"[73] भारत ने देंग के प्रस्ताव को पूरी तरह नहीं परखा था। 1985 में चीन ने पैकेज डील के प्रति अपने रवैये को बदल दिया। एक पूर्व विदेश सचिव, जो सीमा संबंधी बातचीत में करीब से जुड़े थे, उन्होंने "रुख में कठोरता" की बात कही।[74] चीन का दावा था कि भारत ने देंग के शब्दों को सही ढंग से नहीं समझा।[75]

कई सवाल बचे रहते हैं। 1974 और 1984 के बीच चीन ने बेहतर रिश्ते और सीमा-संबंधी मुद्दों के हल के लिए ज़ोर क्यों दिया? माओ के बाद, क्या यह चीन की नई भारत नीति का संकेत था? 1985 के बाद इस प्रस्ताव से चीन पीछे क्यों हट गया?

चीन के विदेश मंत्री के अनुसार, 1978 में जब देंग चीन के सर्वोच्च नेता बने, तो उनके तीन मूल उद्देश्य थे: सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन के राजनयिक अलगाव को खत्म करना, आधिपत्य विरोधी सोच को संयमित करना और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना जिससे आर्थिक सुधार के लिए सही ज़मीन तैयार की जा सके। चीन दोनों महाशक्तियों को आधिपत्य स्थापित करने वाला मानता था लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोवियत संघ ज़्यादा बड़ा खतरा था।[76] इसकी वजह थी सीमा पर सुरक्षा बलों का जमावड़ा (जिसमें मंगोलिया और उत्तरी सीमा के पास 10 लाख सोवियत सैनिक शामिल थे), 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमला, और इंडो-चाइना क्षेत्र में सोवियत संघ की उपस्थिति जिसने घेराव के डर को फिर से जगा दिया था।[77] अपनी जीवनी में हुआंग हा ने दावा किया है कि "सोवियत सेना के अफगानिस्तान में हमले के साथ-साथ कंबोडिया के खिलाफ युद्ध में वियतनाम के समर्थन ने सोवियत संघ को उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से चीन का घेराव करने में सक्षम बना दिया था।"[78] देंग ने कहा, "सोवियत संघ की तेज़ी से बढ़ रही सामरिक तैनाती ने विश्व शांति और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है।"[79] इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने विकासशील देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की।[80] भारत की भू-राजनीतिक स्थिति और विकासशील देशों के बीच भारत का प्रभाव, चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन गया। 1979 और 1984 के बीच संबंधों को सुधारने और भारत से दोस्ती के प्रस्ताव का दौर और सोवियत संघ से चीन को खतरे की आशंका की अवधि मेल खाती है।

इस परिकल्पना का समर्थन 1979 और 1982 के बीच चीन के प्रस्तावों की भाषा भी करती है। फरवरी 1979 में देंग ने भारतीय पत्रकारों को कहा, "विश्व में कई जगह उथल-पुथल मची हुई है और यह एशिया के लिए भी लागू होता है। एक ओर वर्चस्ववादी (यानी, सोवियत संघ) दक्षिण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और यह चिंता का विषय है।"[81] इस साक्षात्कार के कुछ दिनों बाद ही, जून 1980 में, शिन्हुआ की एक टिप्पणी में यही बात दोहराई गई।[82] और 1982 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी मुलाकात में देंग ने कहा था कि चीन और भारत एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं है और उन्होंने दोनों देश के बीच मतभेदों को गंभीर नहीं करार दिया। चीन के सर्वोच्च नेता के कहे ये शब्द उस दौर से हैं जब चीन को सोवियत संघ से सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा था। इससे निपटने के लिए चीन कई मुद्दों पर समझौता करने को तैयार था।

लेकिन, 1980 के दशक के मध्य तक, सोवियत संघ में कहानी बदल रही थी और अमेरिका के साथ चीन के रिश्तों में भी खटास सी आने लग गई थी। चीन के नेताओं को लग रहा था कि ताइवान मामले पर अमेरिका "दोनों-ओर" से खेलने की कोशिश कर रहा है।[83] देंग ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से साफ कह दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे द्वीप में शस्त्रों की बिक्री बढ़ जाए, साथ ही, ताइवानी सरकार को ऐसा कोई बहाना ना दिया जाए कि वह चीन के साथ विलय की बातचीत शुरू ना करे।[84]

अप्रैल 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान संबंध अधिनियम को पारित किया जिसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को निराश कर दिया। अमेरिका के "वन चाइना" नीति के प्रति राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की प्रतिबद्धता पर भी बीजिंग को शक था,[85] और उसे यकीन हो गया कि अमेरिका "वन चाइना, वन ताइवान" नीति पर चलना चाहता है।

1982 में ताशकंद में जब सोवियत संघ के महासचिव लियोनिड ब्रेज़नेव ने चीन से रिश्ते सुधारने के संकेत दिए [86], तब देंग ने इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लिया।[87] 1984 में उन्होंने मॉस्को को संदेश भेजा कि चीन "स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष"[88] रहेगा। 1985 में केंद्रीय सैन्य आयोग को दिए गए एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि

> पिछले कुछ वर्षों में सोवियत संघ के वर्चस्व के खतरे की वजह से, हमने जापान से लेकर यूरोप और अमेरिका तक, एक कूटनीतिक रक्षापंक्ति बनाई थी। लेकिन अब हमारी नीति में बड़ा बदलाव आया है। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से रिश्ते सुधारे हैं। चीन किसी देश के अनुसार नहीं चलेगा और ना ही किसी देश को चीन का लाभ उठाने देगा।[89]

यह बताता है कि 80 के दशक के अंत तक, चीन की विदेश नीति में महाशक्ति त्रिकोण के साथ संबंधों के दृष्टिकोण से बदलाव आ गया था। जैसे-जैसे सोवियत संघ के साथ चीन के रिश्ते सुधरते गए, वैसे-वैसे भारत से दोस्ताना संबंध बनाने की ज़रूरत भी कम होती गई। हालांकि, निश्चित रूप से यह कहने के लिए हमें चीन के आधिकारिक अभिलेखों के सामने आने का इंतज़ार करना होगा, लेकिन, यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि 1979-1982 के बीच भारत के साथ दोस्ती प्रस्ताव और 1985 के बाद इस रवैये में बदलाव की वजह महाशक्तियों के साथ चीन के संबध थे ना कि द्विपक्षीय नीति में बदलाव।

1979 और 1988 के बीच भारत की चिंता के विषय, जैसे कि पाकिस्तान पर चीन के रवैये का ना बदलना भी इसी ओर संकेत देता है। सैन्य, परमाणु-संबंधी और सामरिक मुद्दों पर चीन पाकिस्तान की सहायता करता रहा और पश्चिमी देशों के सामने भारत के मुकाबले उसी का समर्थन किया। भले ही देंग ने वाजपेयी से पाकिस्तान से संबंध बेहतर करने को कहा हो, लेकिन, वाजपेयी के दौरे से पहले, उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों[90] से पाकिस्तान की मदद बढ़ाने का आग्रह किया था क्योंकि "पाकिस्तान को भारत के साथ-साथ उत्तर से (अफगानिस्तान में सोवियत संघ की उपस्थिति) से भी खतरा था।"[91] पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र कार्यक्रम पर आपत्तियों को दूर करने के लिए चीन ने अमेरिका को प्रोत्साहित किया था।[92] इन उदाहरणों से यह साबित होता है कि चीन की भारत-नीति में कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं आया था।

1980 के दशक के अंत तक चीन और सोवियत संघ के रिश्तों में सुधार आ गया था, और इसी के साथ-साथ भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा था। 1986 में चीनी सेना की सुमडुरोंगछू घाटी में घुसपैठ, भारत का जवाब और 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ, एक बार फिर सीमा विवाद जीवित हो उठा। तनाव के इस दौर के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिसंबर 1988 में चीन का दौरा किया और इसके बाद रिश्तों में फिर से गरमाहट आने लग गई। चीनी विशेषज्ञ दावा करते हैं कि सोवियत संघ से चीन के बेहतर संबंधों की वजह ने भारत को रिश्तों को सुधारने के लिए मजबूर किया।[93] मैंने पहले भी कहा है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के पास वजहें थीं।[94] चीन के नेतृत्व के बारे में सीमित जानकारी की वजह से निर्णायक तरीके से यह कहा नहीं जा सकता है कि देंग की अगुवाई में चीन की भारत नीति (जो माओ के दौर के लिए भी सही है) की संरचना महाशक्तियों के प्रभुत्व के दृष्टिकोण से बनाई गई, लेकिन, 1980 के दशक में चीन की भारत नीति में उतार-चढ़ाव और रूस के साथ निरंतर बदलते रिश्तों में सिर्फ संयोग नहीं दिखता है।

1988 में जब राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया तो वो 1960 के बाद पहली बार दोनों में से किसी भी देश के प्रमुख द्वारा की गई द्विपक्षीय यात्रा थी। रिश्तों को सुधारने के लिए यह यात्रा एक नए मौके की तरह सामने आई। द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा, चीन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के त्रिकोणीय संबंध भी बदलाव के कगार पर थे। देंग ने गांधी को कहा कि

> विश्व में समीकरण बदल रहे हैं… वर्चस्व, ध्रुवीकरण और गुटीय समझौतों का दौर खत्म हो रहा है। तब किस आधार पर नए रिश्तों की इमारत को बनाया जाए? पहली है एक नई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संरचना स्थापित करना और दूसरी है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाना।[95]

इस संदर्भ में देंग ने एशियाई सदी की बात कही, और यह भी कहा, कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक भारत और चीन दोनों विकसित ना हों। यह एक संकेत था कि शीत युद्ध को खत्म होता देखकर चीन अपनी विदेश नीति के संतुलन पर फिर से काम करने जा रहा था।

चीन की भारत नीति के दूसरे चरण (जो राजीव गांधी के 1988 के दौरे के साथ खत्म हुआ) से तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहली, उपलब्ध जानकारी इस ओर इशारा करती है कि उसकी भारत नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था और यह अभी भी महाशक्तियों के त्रिकोणीय संबंधों से प्रभावित था। दूसरी, एक सहायक विदेश नीति बनाई गई थी जिसका मकसद चीन को अतिरिक्त सुरक्षा देना था और वह थी भारत को नियंत्रण में रखने के लिए पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में तैयार करना। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी और 1988 के बाद भी चलती रही। तीसरी यह कि चीन ने तब-तब भारत के करीब आने की कोशिश की, जब-जब यह लगने लगा कि उसे भारत से खतरा बढ़ सकता है। मूलत: यह कहना गलत नहीं होगा कि देंग के कार्यकाल के दौरान चीन की विदेश नीति में भारत को स्वतंत्र शक्ति केंद्र या व्यक्तिगत खतरे की तरह नहीं, बल्कि सहायक शक्ति के तौर पर देखा गया जिसे मनाकर या फिर धमकाकर तब-तब संभाला जा सकता था, जब-जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चीन के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ता। बाकी समय चीन, नरम तरीके से ही सही भारत की उपेक्षा ही करता था।

## शीत युद्ध के बाद चीन की भारत नीति

शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व समीकरण को पूरी तरह बदल दिया और इसलिए चीन और भारत दोनों देशों को अपनी विदेश नीति को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर यूरोप में साम्यवाद के खात्मे का खतरा भी मंडरा रहा था और इससे उसके अस्तित्व पर भी काले बादल छा सकते थे। 1989 में त्यानआनमेन चौक कांड के बाद, पश्चिमी देशों द्वारा चीन के बहिष्कार ने इन ख्यालों को और मज़बूती दी। देंग ने पश्चिम की इस नीति को "बगैर बंदूकों के विश्व युद्ध"[96] करार दिया। सीसीपी यह मानती थी कि पश्चिमी शक्तियां चीन को उथल-पुथल की स्थिति में देखना चाहती थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन के "मुख्य विरोधी"[97] के तौर पर देखा गया, लेकिन सीसीपी को इस बात का भी अहसास हो गया था कि विश्व अब एकध्रुवीय हो गया है। इस नई दुनिया में चीन ने अपनी जगह बनाने के लिए मुख्यत: तीन मुद्दों पर अपनी विदेश नीति गढ़ी: संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उपयोगी साबित होना, सीमा को सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाना, और विकासशील देशों के साथ और गहरे रिश्ते बनाना जिससे उसकी उभरती महाशक्ति की छवि को ठेस ना पहुंचे। सोच यह थी कि शक्ति का एक नया वैश्विक संतुलन बनने तक पैंतरे बदलने और सुरक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए।

उस वक्त के सीसीपी के महासचिव, जियांग ज़ेमिन, ने 1989 में कहा, "चीन कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा नहीं रहा है, बल्कि चीन एक विशाल बाज़ार है और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहकारिता के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।"[98] उन्होंने यह भी कहा कि "एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के हित पारस्परिक हैं और क्षेत्र के विकास और स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच मिलता महत्वपूर्ण है"।[99] संदेश यह था कि एशिया में व्यवस्था बनाए रखने में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।[100] यह गौर करने की बात है कि चीनी राजनेताओं ने शायद ही किसी और देश का जिक्र किया था, जो इस काम में चीन का हाथ बंटा सकते थे। जब-जब चीन को लगा कि उसके प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है, जैसा कि 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद हुआ, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका से हाथ मिलाकर अपने रुतबे का अहसास दिलाने की कोशिश की।[101]

चीन की दूसरी प्राथमिकता थी अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना और विकासशील देशों के बीच अपनी छवि सुधारना। 1993 में सेना को संबोधित करते हुए, जियांग ने कहा था कि अगर क्षेत्र में शांति बनाए रखनी है तो "हमें पड़ोसी देशों में स्थिरता बनाए रखने पर ज़ोर देना होगा, शंकाओं को दूर करना होगा, और पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने होंगे।"[102] सुरक्षा की चिंता ने चीन को रूस, मध्य एशियाई देशों, वियतनाम और भारत के साथ सीमा को स्थिर बनाने पर मजबूर किया। इसी के साथ, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी छवि को बेहतर बनाने में भी चीन जुट गया। 1990 के बाद, भारत और चीन के संबंधों को शीत युद्ध की समाप्ति के बाद चीन की बदलती प्राथमिकताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

उस वक्त चीन की नज़रों में भारत का महत्व इसलिए था क्योंकि भारत ना सिर्फ एक परिधीय देश था, बल्कि विकासशील देशों के बीच भारत का काफी प्रभाव भी था। राजीव गांधी के दौरे ने दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बना दिया था और त्यानआनमेन चौक कांड के बाद, चीन की निंदा में भारत ने पश्चिमी देशों का साथ नहीं दिया था। दोनों देशों का ध्यान आर्थिक विकास पर था। 1988 में राजीव गांधी के दौरे ने सीमा मुद्दों के हल के लिए रास्ता तय कर दिया था और अगर इस पर जल्दी अमल हो जाता तो यह ना सिर्फ चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को कम करता, बल्कि कई दूसरे क्षेत्रों में भागीदारी की बुनियाद भी बनाता। लेकिन, गांधी के दौरे के कुछ महीनों बाद ही, सीसीपी के तत्कालीन महासचिव, जियांग ज़ेमिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश को कहा कि "सीमा पर मतभेद की वजह से चीन और भारत के सहयोग की भी सीमाएं हैं।"[103] भारत के पूर्व विदेश सचिव, जे एन दीक्षित ने अपनी जीवनी में लिखा है कि 1992 में उन्होंने अपने चीनी समकक्ष से इस मुद्दे पर चर्चा की थी लेकिन उन्हें यह संकेत मिला था कि चीन के सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं आया था।[104] एक और विदेश सचिव, श्याम सरन, ने भी लिखा है कि चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग इस सवाल से "बचकर निकल गए" जब 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने उनसे इस मामले पर चर्चा की और देंग के पैकेज डील प्रस्ताव का ब्यौरा दिया।[105] ऐसा प्रतीत होता है कि चीन का लक्ष्य केवल मुद्दों को सुलझाने की संरचना बनाने तक ही सीमित था, जैसे 1993 का सीमा शांति समझौता (Border Peace and Tranquility Agreement of 1993) और 1996 का विश्वास बहाली समझौता (Confidence Building Measures Agreement of 1996)। इन समझौतों ने चीन के इन उद्देश्यों को पक्का कर दिया कि उसकी सीमाओं पर कोई खतरा नहीं आए और चीन विरोधी खेमे में भारत के शामिल होने की संभावनाएं भी घट जाएं।

भारत की दूसरी चिंताओं के बारे में भी चीन का रवैया दर्शाता है कि वो अपनी विदेश नीति में कोई बुनियादी बदलाव करना नहीं, बल्कि खतरों को कम करना चाहता था। उदाहरण के तौर पर, 1990 के बाद, चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की चिंताओं को अनसुना कर दिया।[106] कश्मीर मामले पर, 1996 में जियांग के दौरे के दौरान, चीन ने पाकिस्तान से अपने दृष्टिकोण को बदलने की मांग की, और शायद इसी वजह से 1992 में और कारगिल युद्ध के बाद 1999 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में कोई शोर नहीं मचाया। लेकिन, यह केवल दिखावा भर था। कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका या फिर कश्मीर के भविष्य को लेकर जन-अधिकार के मसले पर चीन की राय कभी नहीं बदली। वो अभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं मानता था, जबकि, तिब्बत और ताइवान के मुद्दों पर वो भारत से समर्थन की उम्मीद रखता था। 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हुए चर्चा में चीन की वजह से ही भारत की भूमिका सीमित रही।[107] संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने की कोशिश के मसले पर चीन ने अपने असली रंग कभी नहीं दिखाए।

1990 की शुरुआत में भारत के साथ चीन के दोस्ताना बर्ताव के पीछे वजह थी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंधों को लेकर शंकाएं और अनिश्चितता। देंग ने अपने उत्तराधिकारियों को आगाह कर दिया था कि अमेरिका उन देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा जो शीत युद्ध के दौरान उसके साथ नहीं जुड़े थे।[108] भारत इस सूची में शामिल था और अमेरिका को रोकने के लिए चीन के लिए उपयुक्त था।[109] चीनी नेताओं के "एशियाई सदी" की बातों को इस संदर्भ में देखना ज़रूरी है। सोच यह थी कि वैश्विक उथल-पुथल के दौरान भारत तटस्थ बना रहे।

शीत युद्ध के बाद, चीन की भारत नीति में कोई बदलाव ना आने के पीछे दो वजह हो सकती है। पहली यह है कि बीजिंग ने कभी भी भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखा ही नहीं, क्योंकि भारत की सीमित क्षमता ने उसे इस तरह देखे जाने लायक नहीं बनाया।[110] इस बात का प्रमाण यह है कि जियांग ने अपने लेखों में महाशक्तियों की चर्चा की है, लेकिन, 1996 के भारत दौरे की चर्चा के अलावा भारत का नाम कहीं नहीं लिया गया है।[111] दूसरा प्रमाण यह है, कि चीन को अनुमान था कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर इतना ज़्यादा था कि दोनों देशों के बीच ऐसी सच्ची

साझेदारी नहीं हो सकती थी जो चीन के लिए खतरा साबित हो सके। इन बातों से यह कहा जा सकता है कि 1990 की शुरुआत में चीन की भारत नीति, एक ध्रुवीय विश्व में चीन पर बने दबावों को कम करने के दृष्टिकोण से बनाई गई थी, लेकिन, सवालों का स्थायी जवाब ढूंढ़ने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी वजह से दोनों देशों के बीच बातचीत उस स्तर पर पहुंच गई जिसे पूर्व विदेश सचिव जे एन दीक्षित ने, 90 के दशक के मध्य में, "निष्क्रिय पठार"[112] करार दिया था।

दूसरा मौका आया 1998 में, जब भारत के परमाणु परीक्षण के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया ने चीन को चौंका दिया। चीनी विद्वानों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एशियाई समीकरणों में नई दिल्ली की नई भूमिका की चर्चा की।[113] इस बात से चिंतित होकर कि भारत एक महाशक्ति की तरफ खिंच सकता है, चीन ने फिर से सीमा संबंधी विषयों पर बातचीत शुरू की और विशेष प्रतिनिधि तंत्र बनाया। इस रिश्ते का चरम आया 2005 में जब बीजिंग और दिल्ली ने यह घोषणा की कि दोनों देश के रिश्तों का चरित्र "वैश्विक और सामरिक"[114] था। लेकिन श्याम सरण के शब्दों में यह "सहमति की समरूपता" कुछ ही समय तक चल सकी।[115] 2000 के पहले दशक के मध्य से, महाशक्तियों के त्रिकोण में चीन की स्थिति सुखद होने लगी और उसकी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में कई गुणा बढ़ गई। इसी वजह से चीन के रवैये में भी बदलाव आने लगा जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पूर्व विदेश मंत्री ली झाओशिंग की यह टिप्पणी, "कभी-कभी चीन की उदारता को कई भारतीय राजनीतिज्ञ उसकी कमजोरी समझते हैं।"[116] भारत के प्रति चीन की सोच का यह सटीक प्रतिबिंब है। 1988-98 तक चीन के विदेश मंत्री और 1992-2003 तक चीन के विदेश नीति के उपाध्यक्ष, क़ियान क़िचेन ने अपनी जीवनी में एक बार भी भारत का जिक्र नहीं किया है और यह दिखाता है कि चीन का उच्च नेतृत्व भारत के साथ संबंधों को रणनीतिक प्राथमिकता में कितना नीचे रखता है। इसी तरह, जियांग ज़ेमिन के लेखों में भी 1989 से 1998 तक के दौर में भारत का जिक्र नहीं है - जबकि दोनों देशों के संबंधों के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण दौर था।

नई सदी के पहले दशक के मध्य तक चीन का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। वजह थी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामान्य होते रिश्ते और रूस के साथ एक नई भागीदारी की शुरुआत। इसने, जैसा कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री ली झाओशिंग ने अपनी जीवनी में लिखा है, "चीन को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपना पक्ष रखने के लिए और पश्चिमी देशों से आने वाले दबाव को बेहतर तरीके से संभालने के लिए ज़्यादा काबिल बना दिया।"[118] 2002 में तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री, क़ियान क़िचेन ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को तोड़ने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन, दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों के टूटने की कीमत चुका नहीं सकता।"[119] कुछ इसी तर्ज पर, रूस और चीन के बीच में इस सदी की शुरुआत में सीमा संबंधी चर्चाओं का ब्यौरा देते हुए पूर्व विदेश मंत्री टैंग जिशुआन ने लिखा है, "चीन और रूस के बीच सीमा संबंधी मुद्दों का सही हल बाकी पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के लिए बेहतरीन मिसाल बन कर उभरा है और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीति के लिए भी इसका बहुत महत्व है, जिससे हम घरेलू आर्थिक विकास के लिए सही हालात बना सकते हैं।"[120] संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रिश्तों के सामान्य होने और रूस के साथ भागीदारी का मतलब था चीन पर दबाव में कमी और चीन के दृष्टिकोण से शक्ति का बेहतर संतुलन। इसी दौरान, भारत और चीन के रिश्तों में तनाव नज़र आने लगा[121] क्योंकि नई दिल्ली में इस बात से निराशा थी कि चीन उसकी चिंताओं को महत्व नहीं दे रहा था। लेकिन, दाई बिंगगुओ, जो 2008-2013 तक चीन के काउंसलर और भारत के साथ बातचीत करने वाले मुख्य कूटनीतिज्ञ रहे, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि दोनों देशों के संबंधों का भविष्य "मौजूदा मतभेदों" से ज़्यादा "रणनीतिक समानताएं" तय करेंगी।[122] यह दर्शाता है कि चीन अभी भी भारत को केवल वैश्विक कूटनीति के चश्मे से ही देख रहा था और दोनों देशों के बीच की दिक्कतों की तरफ उसका ध्यान नहीं था। जब कभी भारत ने चीन का विरोध किया तो उसे तनाव बढ़ाने का दोषी करार दिया गया क्योंकि चीन के प्रति उसकी धारणा गलत थी कि चीन भारत को नुकसान पहुंचाएगा।[123] और चूंकि भारत ने नियमित तौर पर विरोध नहीं किया इसलिए चीन के राजनेताओं को लगा कि उन्होंने "सकारत्मक बातचीत के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का सही तरीका" ढूंढ़ लिया था।[124]

जैसे-जैसे रिश्तों में तनाव बढ़ता गया, खास तौर पर 2013 के बाद, चीनी शोधकर्ताओं ने भारत को बीजिंग की नीयत की गलत व्याख्या करने का जिम्मेदार ठहराया। एक आम धारणा यह दिखाई देती थी कि बीजिंग ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन उसे बदले में कुछ नहीं मिला है।[125] इन लेखों को बारीकी से देखें तो यह पता चलता है कि भारत के अच्छे इरादों को द्विपक्षीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवस्था के संदर्भ में देखा गया। नीचे लिखी गई बातें बार-बार चीन के बयानों में दिखाई देती हैं:

- चीन ने कभी भारत को खतरा नहीं माना है, लेकिन, भारत चीन को खतरा मानता रहा है।
- हिंद महासागर वैश्विक व्यवसाय का महत्वपूर्ण चौराहा और यूरेशिया की सबसे कमजोर कड़ी है, और चीन के हितों के लिए अहम है, लेकिन, चीन की मौजूदगी भारत को व्याकुल कर देती है।[126]
- भारत तिल का ताड़ बनाता है - जबकि चीन को टकराव नहीं बल्कि सामरिक स्थिरता चाहिए।[127]
- चीन के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है।[128]
- चीन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका क्योंकि वो चीन का उत्थान नहीं देख सकता। भारत के साथ रिश्तों में तनाव इसलिए आया है क्योंकि वो चीन के विरुद्ध अमेरिका की पहल में भागीदार बनना चाहता है।[129]
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस चलन में बढ़ोतरी हुई है।[130] उन्होंने भारत के निरपेक्ष रहने की प्रथा को तोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करीबी बढ़ाई है।[131]

इन बातों का मूल मतलब यह है कि भारत कभी चीन की वैश्विक दृष्टि में चिंता का विषय नहीं था, और ना ही चीन उसे कोई खतरा मानता था। दूसरी ओर, भारत चीन को अपनी राह में रोड़ा मानता है और उसे हटाने के लिए उसने अमेरिका का हाथ थाम लिया है। संक्षेप में कहें, तो अमेरिका के साथ भारत की करीबी चीन की परेशानी की वजह है।

चीन के सामरिक और अकादमिक समुदाय द्वारा महाशक्तियों के साथ संबंध के संदर्भ में जो जगह भारत को दी गई है, उसका प्रतिबिंब चीनी राजनेताओं के दृष्टिकोण में भी दिखाई देता है। राष्ट्रपति पद पर हू जिंताओ के कार्यकाल के दूसरे चरण और शी जिनपिंग के पहले कार्यकाल के दौरान, "वैश्विक स्थिरता की धुरी और विश्व का शांतिदूत"[132] बनने के नज़रिए से चीन में अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर सकारात्मक सोच थी। 2013 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात के दौरान, शी ने हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही।[133] संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और साथ ही साथ चीन को विश्व के नए शक्ति केंद्रों की तरह चिन्हित किया गया[134] और इन सभी देशों के साथ, चीन के संबंध अच्छे थे। शक्तिशाली देशों के साथ इन नए रिश्तों से मिले आत्मविश्वास से लैस, चीन के राजनेता भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बोलते रहे और कहते रहे कि "गाड़ी प्रगति की पटरी पर चल चुकी है,"[135] और चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी सुधार के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं।[136] चीनी नेता उन मुद्दों पर प्रकाश डालते रहे जो उनके दृष्टिकोण से रणनीतिक वर्चस्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण थे, और भारत की चिंताओं को वे "स्थानीय" परेशानी कहकर टालते रहे। जब भारत सीमा संबंधी मुद्दों के हल ढूंढ़ने पर ज़ोर डालने लगा तब चीनी नेता यह कहने लगे कि इन विषयों पर अत्यधिक ध्यान दोनों देशों के संबंध को जटिल कर रहा है क्योंकि इनकी वजह से रणनीति से जुड़े मुद्दों की अनदेखी हो रही है।[137] चीन भारत को ही संदेह के कटघरे में यह कहकर डालने की कोशिश करता कि दोनों पक्षों को "द्विपक्षीय संबंध के कुछ खास मुद्दों को बिना उनका राजनीतिकरण किए, चीन- भारत संबंधों में सही जगह पर रखकर नियंत्रित करना चाहिए ताकि चीन और भारत के संबंधों पर इसका असर ना पड़े।"[138] उदाहरण के तौर पर, जब विदेश मंत्री वैंग यी इस लेखक से मिले, तो उन्होंने सद्भाव का भार दिल्ली पर डालते हुए कहा, "आशा है कि भारत सूझ-बूझ के साथ संवेदनशील मुद्दों को संभालेगा।"[139] दूसरी ओर, चीनी हित वाले मुद्दों जैसे कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या फिर बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव पर भारत की प्रतिक्रिया पर, चीनी नेताओं का वक्तव्य हमेशा यही रहा कि बीजिंग की नीयत को सही ढंग से समझने की ज़रूरत है, मतलब, भारत को चीन के रणनीतिक हितों को स्वीकार और समायोजित कर लेना चाहिए।

2018 के बाद, जब यह साफ होने लगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को चुनौती देने का मन बना रहा है, तब शी यह कहने लगे कि रुकावट, दबाव और भिड़ंत की वजह से विश्व शांति को खतरा है।[140] चीन को अमेरिका द्वारा डाले गए दबाव का अहसास हो रहा था। इस दौर को शी ने "उथल-पुथल और परिवर्तन का समय"[141] करार दिया और इसी दौरान भारत की तरफ बर्ताव में भी बदलाव आया। बीजिंग में चर्चा का मुख्य मुद्दा

बना संयुक्त राज्य अमेरिका का चीन के प्रति व्यवहार और वॉशिंगटन के साथ दिल्ली के संबंध। भारत को अब इस बात पर परखा जा रहा था कि वो अमेरिका संबंधी मामलों पर चीन के साथ था या खिलाफ, बगैर इस बात की परवाह किए कि भारत की भी अपनी एक स्वतंत्र सोच हो सकती है। एक टिप्पणीकार ने इस रिश्ते की व्याख्या कुछ इस प्रकार की: "चीन के प्रति पश्चिमी देशों की गलत धारणाओं के संदर्भ में भारत और चीन के संबंधों पर चीन और पश्चिम के रिश्तों के प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।"[142] चीन की नज़रों में भारत की छवि कैसी है, इसका उदाहरण विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी, वैंग वेनबिन, के बयान से मिलता है जिसमें यह कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि भारत "स्वतंत्र ढंग से अपनी नीति बनाएगा।"[143] इस कथन की पृष्ठभूमि है भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर का बयान जिसमें उन्होंने कहा था "स्वतंत्रता…हमेशा से हमारी सोच की धुरी रही है।" इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैंग की टिप्पणी भारत और अमेरिका की नौसेना के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पास एक अमेरिकी विमानवाहक पोत के साथ किए गए युद्धाभ्यास के बाद आई। नए चीनी आकलन में माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका की सेनाओं द्वारा किए समझौते का मतलब है कि दोनों देश संधि की ओर अग्रसर हो रहे हैं,[144] और इससे शक्ति संतुलन बिगड़ा है और सामरिक विश्वास को ठेस पहुंची है।[145] चीन और भारत रिश्तों पर एक मुख्य टिप्पणीकार, ये हैलिन का वक्तव्य है कि चीन ने यह मान लिया है कि भारत का झुकाव संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर होगा ताकि उसे फायदे मिलें और चीन की घेराबंदी करने की कोशिश की जाएगी।[146]

चीन की मौजूदा भारत नीति के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले एक नज़र वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2013 से चल रहे तनाव पर डालना ज़रूरी है। दोनों देशों के रिश्ते में इससे ज़्यादा समय तक किसी भी सीमा रेखा पर तनाव नहीं बना रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह उस समय हो रहा है जब भारत अमेरिका से करीबी बढ़ा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर हमेशा चीन की नज़र रहती है और दोनों देशों में तालमेल बढ़ने से चीन की चिंता बढ़ गई है। चीनी विद्वानों के लेखन और आधिकारिक बयान अमेरिका को चीन का विरोधी बताते हैं और भारत को उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गरमी बढ़ाकर ना सिर्फ चीन भारत को चेतावनी देता है, साथ ही, भू-राजनीतिक विरोध की संभावनाओं को सीमित रखने की कोशिश करता है। यह दावा है केटियान ज़ैंग के एक नए अध्ययन का और वो इस निष्कर्ष पर चीनी अधिकारी और विद्वानों से हुए बातचीत के माध्यम से पहुंची हैं।[147] इसके अनुसार चीनी अनुमान यह है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जो वॉशिंगटन को दिल्ली के समर्थन में दखल देने के लिए मजबूर करें, और इन परिस्थितियों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सैन्य क्षमता, बगैर किसी जवाबी कार्रवाई के, भारत को अस्थिर करने के लिए काफी है। भारत ने सीमा रेखा पर हुए वारदातों के पीछे चीन की नीयत पर आश्चर्य जताया है लेकिन दिल्ली और वॉशिंगटन के बेहतर होते रिश्तों और चीन के साथ भारत के रिश्तों में तनाव के बीच का यह संबंध इस शोध-पत्र की मूल सोच को सही साबित करती है - चीन के दृष्टिकोण में भारत का स्थान रूस, अमेरिका और दूसरी महाशक्तियों के साथ उसके अपने रिश्तों के अनुसार बनता है।

भारत और चीन के संबंधों के तीनों चरण के अध्ययन से चार मूल निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, भारत की ओर चीन की नीति में एक समानता चली आ रही है। चीन भारत को अपने से कम स्तर का मानता है और इसलिए वह उसे स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली देश नहीं मानता है। दूसरा, भारत मुख्य रूप से महाशक्ति संबंधों और विशेष रूप से अमेरिका-चीन संबंधों के संदर्भ में चीन के लिए प्रासंगिक है। दूसरी शक्तियों की घेराबंदी और विरोध का डर चीन की उस सोच को प्रभावित करता है, जिससे वो भारत की कार्रवाइयों और विदेश नीति को देखता है। तीसरा, भारत के प्रति चीन का नज़रिया बेहद संकीर्ण है। वह चाहता है कि चीन की मांगों को भारत वैश्विक विपदा का दर्जा दे और तत्काल उसका हल ढूंढ़ निकाले, जबकि भारत को अपनी चिंताओं को स्थानीय मानना चाहिए जो दोनों देशों में बातचीत के जरिए हल हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि चीन उसकी दिक्कतों को बढ़ा नहीं रहा है। चौथा और आखिरी निष्कर्ष, चीन के राजनेता मानते हैं कि उनकी तुलना में भारत कमज़ोर देश है और इस वजह से उन्हें अपनी नीतियों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नतीजतन, चीन ने कभी भारत से दोस्ती करनी ही नहीं चाही, बल्कि सिर्फ ज़रूरतों के मुताबिक भारत की तरफ हाथ बढ़ाया। लंबे समय तक निष्क्रिय संबंध, और फिर सीमा पर परिस्थितियों को गरमाकर भारत को तटस्थ बनने के लिए मजबूर करना, यही रही है चीन की भारत नीति। सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या चीन की यह रणनीति कारगर साबित होगी या फिर इसका उलटा प्रभाव पड़ेगा?

## चीन की भारत नीति का आकलन और भारत के लिए रणनीतिक सुझाव

चीन की भारत नीति का आकलन करने के लिए 2022 में ज़ियाओयू पू [148]और केटियान ज़ैंग[149] द्वारा प्रकाशित दो अध्ययन, शुरुआत करने के लिए अच्छे बिंदु हैं। ज़ियाओयू पू सही कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हैसियत, देशों के बीच शत्रुता की मूल वजह है और भारत-चीन के रिश्ते इन दोनों मुद्दों से प्रभावित हैं। साथ ही, वो कहते हैं कि शक्ति संतुलन में चीन का बड़ा ओहदा उसे भारत को अनदेखा करने की छूट देता है और यह भी सही है। पर इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि चीन को भारत की हैसियत से ईर्ष्या नहीं होती। बल्कि, चीन का बार-बार यह दोहराना कि वह भारत से ऊंची हैसियत रखता है, यह बताता है कि भारत की भू-राजनीतिक स्थिति और प्रजातांत्रिक संरचना उसे पश्चिमी देशों का करीबी बनने का बेहतर अवसर देती है और भारत के चीन के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभरकर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और यह डर चीन के दिल में घर कर गया है। चीन की नीतियां यह दर्शाती हैं (भले ही चीन ऐसा दिखाना ना चाहता हो) कि भारत के साथ हैसियत की लड़ाई में किसी एक देश के लाभ का मतलब है दूसरे की हानि। ज़ियाओयू पू यह तर्क देते हैं कि चीन का मकसद यह नहीं है और चीन का परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन ना करने का मतलब पूर्ण रूप से अवरोध पैदा करना नहीं है, बल्कि, चीन को लगा होगा कि इन दोनों मुद्दों पर ज़्यादा विचार करने की दरकार है। लेकिन, हाल ही में बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी द्वारा आंतकवादी तत्वों की सूची बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया था और इससे यह प्रमाणित होता है कि बीजिंग मानता है कि भारत के फायदे का मतलब उसका नुकसान है।[150]

ज़ियाओयू पू का कहना है कि ऐतिहासिक घटनाएं एवं घरेलू राजनीति की वजह से चीन की ओर भारत का दृष्टिकोण चीन की तुलना में ज़्यादा नकारात्मक है। लेकिन, इस लेख के शुरुआती चरणों में किए गए विश्लेषण इस कथन को गलत प्रमाणित करते हैं। बीती बातें और चीन की घरेलू राजनीति भी दोनों देशों के रिश्तों पर प्रभाव डालती हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 1962 में भारत के साथ हुए युद्ध की यादों को चीन की आम जनता पर मानसिक दबाव बनाने के लिए आज भी प्रयोग करती है और उन्हें बार-बार यह याद दिलाने का प्रयास करती है कि सिर्फ सीसीपी ही उनकी रक्षा कर सकती है। सीसीपी अक्सर यह दावा करती है कि उसने चीन को दुनिया में उसकी सही जगह दिलाई है और 1962 की कहानी उसके आख्यान के लिए सही बैठती है और चीन की राजनीति में उसकी वैधता बनाए रखने के लिए सीसीपी की कोशिश है। इसलिए मौजूदा स्थिति को बेहतर ना बनाने का दारोमदार जितना भारत का है, उतना ही चीन पर भी है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा सैन्य घुसपैठ का अध्ययन करने के बाद, केटियान ज़ैंग का कहना है कि चीन सोची-समझी नीति के तहत ऐसे कदम उठाता है। मैं उनके इस दावे से सहमत हूं कि चीन को भारत के खिलाफ किसी भी कदम उठाने के लिए कोई बड़ी भू-राजनीतिक कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, और इस वजह से दबाव बनाने के लिए चीन लगातार फौजी तौर- तरीकों से धमकाने का काम करता रहता है। हालांकि, उनका यह दावा है कि 2020 के बाद भी चीन के हथकंडों के जवाब में भारत की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उनके इस निष्कर्ष को दोबारा जांचने की ज़रूरत है। वो इस निष्कर्ष पर चीनी विद्वानों और अर्ध-सरकारी अधिकारियों के साथ की गई बातचीत के बाद पहुंची हैं। इनका तर्क है कि दक्षिण एशिया में इकलौती शक्ति जो प्रभाव डाल सकती है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत कभी भी औपचारिक तौर पर उसका सहयोगी नहीं बनेगा। उनका यह भी मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी सैन्य कार्यवाही में भागीदार नहीं बनेगा क्योंकि यह उस पर एक असहनीय भार होगा। चीन में एक यह दृष्टिकोण भी है कि भारत किसी भी देश के साथ कनिष्ठ मित्र के तौर पर नहीं जुड़ेगा और भारत में स्वतंत्र रूप से विदेश नीति बनाने की प्रथा चली आ रही है। आखिर में, ज़ैंग लिखती हैं कि "क्वाड समूह बनने के बाद भी चीन का मानना है कि भारत और अमेरिका ऐसा कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे जिससे भारत-चीन सीमा पर चीन के लिए सैन्य तनाव का जोखिम बढ़े।"[151] भले ही ज़ैंग ने आने वाले समय में किसी भी समझौते से इन्कार नहीं किया है, उनका मानना है कि इसकी संभावना कम है। इसलिए उनका निष्कर्ष है कि चीन की धमकाने वाली किसी भी सैन्य कार्यवाही के वैश्विक स्तर पर पलटवार की संभावना भी कम है।

अगर चीन के नेता भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर सही भी हैं, तब भी यह जांचना ज़रूरी है कि क्या लद्दाख में घुसपैठ, चीन द्वारा की गई एक रणनीतिक भूल थी। चीन की दो मूल मान्यताएं हैं - भारत छोटी-मोटी घटनाओं का जवाब बड़े पैमाने पर सैन्य तरीके से नहीं देगा और भारत

कभी चीन के खिलाफ गठबंधन नहीं बनाएगा - लेकिन, इन मान्यताओं पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है, खासतौर पर 2020 से भारत की रणनीतिक सोच में हुए बदलाव के संदर्भ में।

सबसे पहली बात यह है कि चीन की भूमिका को लेकर भारत की सोच में जो दुविधा थी, वह अब साफ हो गई है। चीन के बरताव को शत्रुता के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और बेहद कम लोग उसके पक्ष में हैं। गलवान घटना के बाद चीन को लेकर जनता की सोच में भी बदलाव आ गया है।

दूसरी बात यह है कि रणनीतिक संयम की सोच में भी परिवर्तन आया है। भारत सरकार अब जोखिम उठाने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है और इसका उदाहरण हमें अगस्त 2022 में रेजांग ला/रेचिन ला में स्नो लेपर्ड काउंटर ऑपरेशन में दिखा। भारत द्वारा इस प्रकार के जवाब के लिए चीन तैयार नहीं था। इसलिए चीन की इस सोच को बदलने का समय आ गया है कि छोटी-मोटी सैन्य कार्यवाही का कोई जवाब भारत इसलिए नहीं देगा क्योंकि वह शांतिप्रिय देश है।

तीसरी बात यह है कि आने वाले समय में भारत घुसपैठ का जवाब किस स्तर पर देगा, इस पर भी चीन के विद्वानों को दोबारा विचार करना चाहिए। ना सिर्फ पहले की तुलना में भारत मानसिक तौर पर ज़्यादा तैयार है, वह तेज़ी से अपने आप को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी वारदात के लिए सशक्त भी बना रहा है। आने वाले समय में भारत की क्षमता को आज के पैमाने से मापना सही नहीं होगा।

चौथी बात, चीन के खिलाफ भू-राजनीतिक विरोध की संभावना भी बढ़ रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बचे- खुचे अवशेष भी लुप्त हो गए हैं और अब पश्चिमी देशों के साथ करीबी बढ़ाने की राह में कोई रोड़ा नहीं है। यह सच है कि दिल्ली वॉशिंगटन के साथ किसी सैन्य संधि करने का इच्छुक नहीं है, लेकिन, चीन पर दबाव बनाने के कई विकल्प मौजूद हैं। भारत हिंद महासागर में अपने भू-राजनीतिक महत्व और तटीय देशों में अपने प्रभाव के ज़रिए चीन के लिए दिक्कतें बढ़ाने में सक्षम है। इसका एक उदाहरण हमें अगस्त 2022 में मिला जब श्रीलंका के तट पर एक चीनी सर्वेक्षण जहाज आकर रुका।[152] जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, वैसे-वैसे चीन के लिए दिक्कतें बढ़ाने के भारतीय विकल्प भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के बाद भू-राजनीतिक विरोध की कीमत का आकलन चीन को दोबारा करना चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षा पर भी पड़ेगा।

पांचवीं बात, चीन यह मानता है कि अर्थव्यवस्था में बड़े अंतर की वजह से भारत हमेशा चीन से नीचे ही रहेगा और भारत की अर्थव्यवस्था चीन से धीमी ही रहेगी क्योंकि भारत चीनी आयात पर निर्भरता नहीं घटा सकता है। पर यह दोनों बातें गलत साबित हो सकती हैं। कई संकेत मिले हैं कि भारत चीन से ज़्यादा तेज़ी से विकास कर सकता है और चीन पर निर्भरता सीमित करना सरकारी नीति बन सकती है। साथ ही, चीन को यह भी सोचना चाहिए कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर वह विश्व की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो उसे भारतीय बाज़ार की ज़रूरत पड़ेगी।

और आखिर में, चीन अब क्वाड और 2018 के बाद किए गए दूसरे बहुपक्षीय समझौतों के महत्व को समझ रहा है। अब वे केवल "समुद्री झाग" नहीं है जैसा कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था।[153] क्वाड भले ही किसी आधिकारिक गठबंधन में ना बदले, लेकिन, यह उस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, और यह बताता है कि आने वाले सालों में भारत की विदेश नीति को आंकने के लिए बीते हुए कल को मापदंड नहीं बनाया जा सकता है।

इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि चीन को भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर नए सिरे से सोचने की दरकार है। फिलहाल, चीन का भारत को किसी खतरे की तरह ना देखने[154] का मतलब यह नहीं है कि वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों में भारत का कोई प्रभाव नहीं है, उसे बराबरी का दर्जा और सम्मान नहीं दिया जाए। बड़ी शक्ति होने के नाते चीन पर यह जिम्मा है कि वह इस रिश्ते को फायदे-नुकसान के समीकरण तक फिसलने ना दें।

## नीतिगत सुझाव

चीन की नीति को प्रभावित करने के लिए भारत क्या कर सकता है? शुरुआत इस बात से करनी चाहिए कि हो सकता है कि भारत के प्रति चीन का रवैया उसकी 'पार्टी ही देश है' की संरचना में घर कर गया हो। अपने आप को बड़ा दिखाने की चीन की आदत और साथ ही, भारत की नीयत पर चीन के शक करने के स्वभाव के मद्देनज़र, दिल्ली को यह बात मान लेनी चाहिए कि दोनों देशों में सामरिक स्पर्धा जारी रहेगी और भारत- चीन संबंधों में इसकी भूमिका और भी विस्तारित हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की उम्मीद भारत को तब तक नहीं रखनी चाहिए, जब तक शक्ति समीकरण में बदलाव नहीं आता है। यह तब होगा जब भारत की अर्थव्यवस्था और विकसित होती है, उसकी कूटनीति बहुआयामी बनती है, और उसकी सैन्य और प्रौद्योगिकी क्षमताएं काफी तेज़ी से बढ़ जाती हैं। इन बदलावों के संकेत तो मिल रहे हैं लेकिन पूरी तरह विकसित होने के लिए कम से कम एक दशक का समय लगेगा। यह दशक बहुत चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि शक्ति समीकरण में कमजोर होने की वजह से भारत को चीन के हथकंडों को झेलना पड़ेगा।

इन परिस्थितियों में भारत को विश्वसनीय और पारदर्शी रूप से संकेत भेजने की ज़रूरत है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब भारतीय नेतृत्व द्वारा दिए गए बयानों में भारत के पक्ष को मुख्य स्थान दिया जाने लगा है (इनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमा संबंधी मामले शामिल हैं) और कहा जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में तनाव तब तक बना रहेगा जब तक चीन इन मुद्दों का हल नहीं निकालता है। भारत को लगातार ऐसे ही संकेत देते रहना चाहिए। इससे भले ही चीन की दिशा ना बदले, पर इससे यह साफ हो जाता है कि भारत चुप बैठने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए घुसपैठ के मामलों को संभालने के लिए बेहतर स्थिति में है। लेकिन, सिर्फ सेना का तैयार होना, चीन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तिब्बत में चीन द्वारा स्थापित आधुनिक शस्त्र संरचना के जवाब में भारत को भी अपनी क्षमताओं को बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। लागत विश्लेषण के बाद कूटनीति, सैन्य और आर्थिक माध्यमों के बीच तालमेल की भी बहुत ज़रूरत है। इसके लिए सरकार के सारे विभागों का सुर एक ही होना चाहिए और अभी तक यह पूरे तौर पर हुआ नहीं है।

गलवान घटनाक्रम ने दिखा दिया है कि भारत के शांतिप्रिय स्वभाव और किसी भी प्रकार के टकराव को टालने के लिए उठाए गए कदम चीन को रोकने के लिए काफी नहीं हैं, जो मानता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसकी स्थिति मज़बूत है। मौजूदा परिस्थिति में जहां एक देश की सेना, दूसरी की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है, वहां भारत को आकलन करना चाहिए कि उसे किस जगह से ज़्यादा खतरा है और वहां सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यह शांति और सद्भावना की तलाश करने से गुणात्मक रूप से अलग है - जोखिम प्रबंधन ज़मीनी कार्यवाही पर से फोकस हटाकर उसे राजनीति और कूटनीतिक कार्यवाही की तरफ ले जाता है। इस स्तर पर बातचीत से टकराव के खतरे को एक अवांछनीय सीमा तक बढ़ने से रोका जा सकता है।

इसलिए दोनों देशों के बीच 2019 से स्थगित बातचीत के सिलसिले को दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। यह बेहद विकट स्थिति है जहां दो परमाणु शक्तियां, जो पड़ोसी भी हैं, वे एक दूसरे से बात ना करें। इस सिलसिले को जल्द से जल्द शुरू करने की दरकार है, भले ही चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के लिए कोई कदम ना उठा रहा हो। दोनों ही पक्षों के लिए पहले हाथ बढ़ाना कठिन होगा, लेकिन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है खासतौर पर इस दशक में जहां दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज़ी से बढ़ेगी।

चीन की तरफ से सार्वजनिक और निजी बयानों से यह प्रतीत होता है कि 3 मुख्य बिंदुओं की मदद से दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम किया जा सकता है। पहला, भारत और चीन को हमेशा बातचीत का ज़रिया खुला रखना चाहिए। दूसरा, दोनों पक्षों के विकास लक्ष्य के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए, और तीसरा, तनाव को बढ़ाए बगैर मतभेदों को सुलझाना आना चाहिए।[155] ये उद्देश्य बहुत अच्छे हैं लेकिन चीन को हमेशा अपना ही पक्ष देखने की आदत है। भारत के हितों को महत्व ना देने की वजह से बातचीत बेहद मुश्किल हो जाती है और गलतफहमी को जन्म देती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि चीन भारत को वैश्विक शक्ति के तौर पर नहीं देखता है और अगर इस स्थिति को सुधारना है तो दोनों देशों के बीच

रणनीतिक संवाद के दायरे को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, साथ ही विकास के लक्ष्यों में भी तालमेल बनाना होगा, ताकि बातचीत के उद्देश्यों के लिए दोनों पक्षों के बीच बराबरी दिखे।

अगर चीन के राजनेताओं के बयानों की जांच की जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन ने कभी भारत को वैश्विक शक्ति का दर्जा दिया ही नहीं, केवल एशिया- प्रशांत क्षेत्र की बड़ी शक्ति के रूप में देखा है। एशिया- प्रशांत क्षेत्र में चीन की नीतियों पर जारी 2017 का राज्य परिषद का प्रतिवेदन यह मानता है कि यह क्षेत्र चीन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और चीन को इस क्षेत्र में स्थित मुख्य देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने चाहिए। इस सूची में भारत के अलावा रूस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इस मुद्दे को बातचीत का केंद्रीय सिद्धांत बनाने की संभावनाओं को खंगालना चाहिए। यह करने के लिए दोनों पक्षों को अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। भारत को यह स्वीकार करना पड़ सकता है कि उसकी राष्ट्रीय शक्ति अभी इतनी नहीं है कि वह चीन पर इस बात का दबाव डाल सके कि चीन उसके साथ वैश्विक समकक्ष के समान व्यवहार करे। चीन को यह मानना पड़ सकता है कि एशिया-प्रशांत/हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक ऐसा शक्ति त्रिकोण है जिसमें रूस शामिल नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी, इस त्रिकोण का सबसे मजबूत कोना हैं, जबकि चीन दूसरे और भारत तीसरे कोण पर है। आने वाले सालों में कोई भी और देश या फिर देशों का समूह इन तीनों से किसी की जगह नहीं ले सकता है, चाहे वह रूस हो, आसियान देश हों या फिर खाड़ी के देश। इनमें से कोई भी समूह अपनी आर्थिक ताकत और सैन्य क्षमता के ज़रिए भी इन तीन खिलाड़ियों में से किसी की जगह नहीं ले सकता है।

आने वाले दशकों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है, और चीन की समृद्धि एवं शक्ति इससे आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए बीजिंग को अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की ज़रूरत है और इस क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका को स्वीकार करने की ज़रूरत है। मार्च 2022 में, जब 2020 के पूर्वी लद्दाख घटनाक्रम के बाद, पहली बार चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कहा था कि चीन "इस क्षेत्र में भारत के ऐतिहासिक समय से निभाए गए किरदार का सम्मान" करता है और "दक्षिण एशिया में 'चीन- भारत प्लस' नीति पर काम करने को तैयार है"[156] इतिहास गवाह है कि ऐसी कथनी कभी करनी में बदली नहीं है। फिर भी, चीन के भारत को क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर देखने से दोनों देशों के बीच सामरिक मुद्दों पर बेहतर बातचीत संभव हो सकती है जिससे सुरक्षा एवं विकास के लक्ष्यों पर तालमेल बनने की उम्मीद जगेगी। इससे प्रतिस्पर्धा को एक का नफा तो दूसरे का नुकसान समझने वाले दृष्टिकोण में भी बदलाव आएगा। यह इसलिए संभव है क्योंकि वैश्विक स्तर पर दोनों देशों के बीच ताक़त का जो अंतर है, वह अंतर भारत-प्रशांत क्षेत्र में कम हो जाता है और इसकी वजह है उत्तरी हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक और राजनीतिक पकड़ का मज़बूत होना।

## निष्कर्ष

इस पत्र का तर्क है कि जब से चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई है तब से उसने भारत को रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्तियों की तुलना में कम महत्व दिया है। रूस और अमेरिका के साथ संबंधों के उतार-चढ़ाव का असर भारत-चीन के रिश्तों पर भी पड़ा है। चीन के इस दृष्टिकोण के पीछे वजह है उसकी यह सोच कि वैश्विक संदर्भ में भारत की हैसियत उससे कम है और उससे चीन को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है और इस वजह से चीन ने भारत के साथ संबंध को द्विपक्षीय दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए भारत को चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका को उभारते हुए दोनों देशों के संबंध की द्विपक्षीय प्रवृत्ति पर ज़ोर देना चाहिए। साथ ही, भारत के पास चीन द्वारा सुरक्षा उल्लंघनों का जवाब देने के लिए तैयारी करने का विकल्प भी मौजूद है। सेना का सशक्तिकरण और बहुआयामी कूटनीति पर जो कदम उठाए गए हैं, उन पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। यह प्रक्रिया आने वाले पांच से दस सालों तक चलाते रहनी होगी, साथ ही दूसरे देशों के साथ मित्रता और घरेलू आर्थिक विकास को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि चीन को भारत के प्रति उसकी नीति में बदलाव करने और भारतीय चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूर किया जा सके। उत्तरी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर असर डालने के लिए भारत को अपनी और दूसरे देशों के साथ तालमेल बनाकर उनकी क्षमता को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए, और चीन को इस मामले में एक सही रणनीतिक फैसला लेने के लिए मजबूर करना चाहिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह दृष्टिकोण सफल होगा लेकिन ऊंचे दांव

को देखते हुए इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। भारत को बातचीत के माध्यम से, चीन की भारत नीति को पारस्परिक रूप से और अधिक संतोषजनक दिशा में ले जाने का प्रयास जारी रखते हुए भी, मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए।

## लेखक का परिचय

**विजय गोखले** कार्नेगी इंडिया में नॉन-रेसिडेंट सीनियर फेलो हैं। गोखले जनवरी 2020 में भारतीय विदेश सेवा से 39 साल के राजनयिक करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए। जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक उन्होंने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया।

विदेश सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के पहले, गोखले ने जनवरी 2010 से अक्टूबर 2013 तक मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में, अक्टूबर 2013 से जनवरी 2016 तक फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में, और जनवरी 2016 से अक्टूबर 2017 तक चीन में भारत के राजदूत के रूप में काम किया था। उन्होंने जुलाई 2003 से जनवरी 2007 तक ताइवान में भारत-ताइपे एसोसिएशन के प्रमुख के तौर पर काम किया है। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पूर्वी एशिया विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है, जिनमें मार्च 2007 से दिसंबर 2009 तक पूर्वी एशिया के लिए संयुक्त सचिव (महानिदेशक) का पद भी शामिल है।

उन्होंने चीनी राजनीति और कूटनीति पर खास महारत के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मामलों पर काफी काम किया है। विदेश सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से, गोखले ने दि न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉरेन पॉलिसी, दि हिंदू, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, और दि इंडियन एक्सप्रेस के लिए लेख लिखे हैं। उन्होंने हाल ही में तीन किताबें भी लिखी हैं : त्यानआनमेन स्क्वैयर : दि मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट (हार्पर कॉलिंस इंडिया, मई 2021), दि लॉन्ग गेम: हाउ दि चाइनीज़ निगोशिएट विद इंडिया (पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, जुलाई 2021), और आफ्टर त्यानआनमेन: दि राइज़ ऑफ चाइना (हार्पर कॉलिंस इंडिया, सितंबर 2022)।

## आभार

लेखक शिवशंकर मेनन और श्रीनाथ राघवन का उनकी पैनी दृष्टि वाली टिप्पणियों और सलाह के लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस शोध पत्र को बेहतर किया है। वो शोध में सहायता और पुराने मसौदों पर मददगार संपादकीय टिप्पणियों के लिए साहेब सिंह चड्ढ़ा का भी धन्यवाद करते हैं।

## नोट्स


1. Zhang, Ketian. “Explaining Chinese Military Coercion in Sino-Indian Border Disputes.” *Journal of Contemporary China*, (June 16, 2022): 1–18. https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2090081.
2. Pu, Xiaoyu. “The Status Dilemma in World Politics: An Anatomy of the China–India Asymmetrical Rivalry.” *The Chinese Journal of International Politics* 15, no. 3 (September 1, 2022): 227–45. https://doi.org/10.1093/cjip/poac015.
3. Zedong, Mao. 1938. “On the New Stage.” *In Collected Works of Mao Tse-tung* (1917-1949). Vol. 6. 9 vols. 129-189. United States: Joint Publication Research Service.
4. Zedong, Mao. 1942. “Celebrating the 24th Anniversary of the Red Army.” In Collected Works of Mao Tse-tung (1917-1949). Vol. 8. 9 vols. 111. United States: Joint Publication Research Service.
5. Zedong, Mao. 1943. “Speech at a Cadres Soiree in Yenan in Celebration of the October Revolution Anniversary.” *In Collected Works of Mao Tse-tung* (1917-1949). Vol. 9. 9 vols. 151. United States: Joint Publication Research Service.
6. Zedong, Mao. “On Coalition Government.” Selected Works of Mao Tse-tung, April 24, 1945. https://www. marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-3/mswv3_25.htm.
7. Enlai, Zhou. 1946. “The Past Year’s Negotiations and the Prospects.” In Selected Works of Zhou Enlai. Vol. 1. 2 vols. 280-292. Beijing: Foreign Languages Press.
8. Zedong, Mao. “Revolutionary Forces of the World Unite, Fight Against Imperialist Aggression!” Selected Works of Mao Tse-tung, November 1948. https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/ volume-4/mswv4_44.htm.
9. Enlai, Zhou. 1949. “Report on Problems Concerning the Peace Talks.” *In Selected Works of Zhou Enlai*. Vol. 1. 2 vols. 352-364. Beijing: Foreign Languages Press.
10. Mao, Zedong. “Mao Zedong, ‘On the People’s Democratic Dictatorship: In Commemoration of the Twenty-eighth Anniversary of the Communist Party of China,’” June 30, 1949. Translation from Selected Works of Mao Tse-tung, Vol. 4 (Peking: Foreign Languages Press, 1961), 411-423. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/119300.
11. Nehru, Jawaharlal. *A Bunch of Old Letters: Written Mostly to Jawaharlal Nehru and Some Written by Him.* (Jawaharlal Nehru Memorial Fund. 1988). 385-386. http://archive.org/details/bunchofoldletter00nehr.
12. Samarani, Guido. “Shaping the Future of Asia: Chiang Kai-Shek, Nehru and China-India Relations During the Second World War Period.” *Working Papers in Contemporary Asian Studies*, 2005. https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/4a2cb270-f70e-41fb-88bf-a686976524d8.
13. Zedong, Mao. 1942. “Essential Points of Speech on Second Imperialist War.” *In Collected Works of Mao Tse- tung (1917-1949)*. Vol. 7. 9 vols. 14-24. United States: Joint Publication Research Service. शायद इकलौता उदाहरण जब माओ ने भारत का ज़िक्र किसी सकारात्मक संदर्भ में किया, वह अप्रैल 1945 में था, जब उन्होंने कहा: “हमें आशा है कि भारत को आज़ादी मिलेगी। क्योंकि एक आज़ाद और लोकतांत्रिक भारत ना सिर्फ भारतीय लोगों की ज़रूरत है बल्कि विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है।” See Zedong, Mao. “On Coalition Government.” *Selected Works of Mao Tse-tung*, April 24, 1945.
14. Snow, Edgar. “Interviews With Mao Tse-Tung by Edgar Snow.” Interviews with Mao Tse-tung, 1936. https://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/1936/11/x01.htm.
15. China. Foreign Ministry. “Report from the Chinese Foreign Ministry, ‘The Asian-African Conference.’” Note, April 1, 1955. PRC FMA 207-00086-03, 14-19. Obtained by Amitav Acharya and translated by Yang Shanhou. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/ document/112893.
16. Doc. 0751, Chinese Version of the talks between Nehru and Mao Tse-Tung, Minutes of Mao Tse-tung’s Second Meeting with Nehru, Peking, October 23, 1954, Yinantan, Zhongnanhai, source: Chinese Foreign Ministry PRC FMA 204-00007-15(1). India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 2. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 1305-1306.
17. Zedong, Mao. 1943. “Comrade Mao Tse-tung Sums Up at 1 July Cadres Soiree the Heroic Struggle of 22 Years.” *In Collected Works of Mao Tse-tung (1917-1949)*. Vol. 9. 9 vols. 140-145. United States: Joint Publication Research Service.

18. Pan Jingguo, Literature Research Office of the CPC Central Committee, Contemporary History Studies, Chinese Lib. Clas. No. D829-351; Doc ID Code: A 1005 4952(2008) 01-0097-09. नेहरू ने आधिकारिक चीनी मीडिया में इस तरह की आलोचना को "एक विजयी क्रांति का उत्साह" कहकर खारिज़ कर दिया। See Doc. 0133, Letter from Prime Minister to Indonesian President, December 22, 1949. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 1. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018), pp. 206-208.
19. Doc. 0133, Letter from Prime Minister to Indonesian President, December 22, 1949. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 1. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 206-208.
20. Mao, Zedong. "Mao Zedong, 'On the People's Democratic Dictatorship: In Commemoration of the Twenty-eighth Anniversary of the Communist Party of China,'" June 30, 1949. Translation from Selected Works of Mao Tse-tung, Vol. 4 (Peking: Foreign Languages Press, 1961), 411-423. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/119300.
21. Doc. 0107, Telegram from Bharat, Nanking to Foreign, New Delhi, November 04, 1959, on Chinese Press Reactions to Nehru's visit to the US in October 1959. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 1. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 163-164.
22. Yudin, Pavel F., Shaoqi Liu, Zedong Mao, and Enlai Zhou. "Report from P. F. Yudin to I. V. Stalin on Meetings with the Leaders of the Communist Party of China, including Mao Zedong on 31 December 1950," January 20, 1951. ARAN, f. 1636, op. 1, d. 199, ll. 1-6, and RGASPI, f. 558, op. 11, d. 345, ll. 0010-0014. Published in Istoricheskii Arkhiv No 4 (2006): 15-19. Translated by Sergey Radchenko. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/122032.
23. Zedong, Mao. 1942. "Essential Points of Speech on Second Imperialist War." *In Collected Works of Mao Tse-tung (1917-1949)*. Vol. 7. 9 vols. 14-24. United States: Joint Publication Research Service.
24. चीन ने भारत और बर्मा को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की श्रेणी में रखा। दक्षिण एशिया वाक्यांश भौगोलिक वर्गीकरण का बाद का रूप था। Enlai, Zhou. 1952. "Report on Problems Concerning the Peace Talks." In *Selected Works of Zhou Enlai.* Vol. 2. 2 vols. 94. Beijing: Foreign Languages Press.
25. Lui, Xuecheng. *The Sino-Indian Border Dispute and Sino-Indian Relations*. Lanham, MD: University Press of America, 1994.
26. Doc. 0088, Telegram from Indembassy, Nanking, to Foreign, New Delhi, 10 August, 1949. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 1. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 127. 1949 में, संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में गैर-साम्यवादी देशों के एक प्रभावी संघ के विकास को प्रोत्साहित कर रहा था जिसे प्रशांत समझौते के रूप में जाना जाता था और वो भारत को इसका हिस्सा बनाना चाहता था।
27. Doc. 0393, Telegram from Indembassy, Peking to Foreign, Part - IV, 07 February, 1952. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 1. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 640.
28. Doc. 0751, Chinese Version of talks between Nehru and Mao Tse-Tung, Peking, October 19, 1954, source: Chinese Foreign Ministry PRC FMA 204-00007-15(1). India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 2. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 1292.
29. Doc. 0338, Ambassador Panikkar's Record of Conversation with Chou En-lai, Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, 02 August, 1951. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 1. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 563-572.
30. Doc. 0751, Chinese Version of talks between Nehru and Mao Tse-Tung, Peking, October 19, 1954, source: Chinese Foreign Ministry PRC FMA 204-00007-15(1). India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 2. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 1291-1292.
31. भारत ने आखिरकार ना तो सैन फ्रांसिस्को शांति समझौते पर दस्तखत किए, और ना ही मनीला सम्मेलन में शामिल हुआ।
32. "अहम बात यह है कि भारत- चीन संबंध अब कुछ अलग और करीबी आधार पर होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम चीन के साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि, यह सच है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के संबंध में हमारी मान्यता और नीति अमेरिका की तुलना में चीन के ज्यादा करीब है।" See Doc. 0716, Letter from Prime Minister to Ambassador Raghavan in Peking, 29 June, 1954. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 2. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 1224.
33. Doc. 0759, Note of Prime Minister Jawaharlal Nehru on the Implications of his China Visit, 14 November, 1954. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 2. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 1372.
34. Doc. 0903, Minutes of the Commonwealth Prime Ministers' Conference relating to "Future Relations with China," 02 July, 1956. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 2. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 1627-1628.

35. Doc. 0393, Telegram from Indembassy, Peking to Foreign, New Delhi, 07 February, 1952. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 1. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 638-642.

36. Zhou, Enlai. "Cable from Zhou Enlai, 'Premier's Intentions and Plans to Visit India.'" Telegram, June 22, 1954. PRC FMA 203-00005-01, 3-4. Translated by Jeffrey Wang. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/112437.

37. China. Foreign Ministry, and Zhen Huang. "Cable from the Chinese Foreign Ministry, 'Receiving the Prime Ministers of India and Other Countries and Attending the Asian-African Conference,'" December 9, 1954. PRC FMA 207-00001-04, 13-14. Translated by Jeffrey Wang. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/114600.

38. China. Foreign Ministry. "Report by the Chinese Foreign Ministry, 'Some Existing Issues in and Suggestions for the Asia-Africa Conference.'" Report, 1955. PRC FMA 207-00004-06, 59-62. Obtained by Amitav Acharya and translated by Yang Shanhou. History and Public Policy Program Digital Archive. https:// digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113179.

39. Zhou, Enlai. "Zhou Enlai's Telegram to the CCP Central Committee and Mao Zedong regarding the Discussion of Political Issues," April 30, 1955. Zhonghua renmin gongheguo waijiaobu dang'anguan, ed., Zhonghua renmin gongheguo waijiao dang'an xuanbian. Di er ji. Zhongguo daibiaotuan chuxi 1955nian Ya Fei huiyi (Selected Diplomatic Archival Documents of the People's Republic of China, Vol. 2: The Chinese Delegation at the 1955 Asia-Africa Conference) (Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 2007), 87-90. Translated for CWIHP by 7Brands. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive. wilsoncenter.org/document/121750.

40. Kalha, Ranjit Singh. *India-China Boundary Issues: Quest for Settlement.* (New Delhi: Pentagon Press, 2014). 97.

41. Khrushchev, Nikita Sergeevich, Yi Chen, Andrei Andreevich Gromyko, Biao Lin, Shaoqi Liu, Zedong Mao, Mikhail A. Suslov, et al. "Discussion between N.S. Khrushchev and Mao Zedong." Memorandum of Conversation, October 2, 1959. Archive of the President of the Russian Federation (APRF), f. 52, op. 1, d. 499, ll. 1-33, copy in Volkogonov Collection, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C. Translated by Vladislav M. Zubok. History and Public Policy Program Digital Archive. https:// digitalarchive. wilsoncenter.org/document/112088.

42. Zhou, Enlai, and G. (Gopalaswami) Parthasarathy. "Memorandum of Conversation: Premier Zhou Receives Indian Ambassador to China Parthasarathy." Memorandum of Conversation, September 30, 1958. PRC FMA 110-00713-02. Translated by Anna Beth Keim. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116576.

43. Khrushchev, Nikita Sergeevich, Yi Chen, Andrei Andreevich Gromyko, Biao Lin, Shaoqi Liu, Zedong Mao, Mikhail A. Suslov, et al. "Discussion between N.S. Khrushchev and Mao Zedong." Memorandum of Conversation, October 2, 1959. Archive of the President of the Russian Federation (APRF), f. 52, op. 1, d. 499, ll. 1-33, copy in Volkogonov Collection, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C. Translated by Vladislav M. Zubok. History and Public Policy Program Digital Archive. https:// digitalarchive. wilsoncenter.org/document/112088.

44. Mao, Zedong. "Mao Zedong, 'On Sino-Indian Relations,'" May 15, 1959. Gang er si Wuhan daxue zongbu et al, eds., Mao Zedong sixiang wansui (Long Live Mao Zedong Thought), vol. 4 (1958-1960) (Wuhan, internal circulation, May 1968): 348-349. History and Public Policy Program Digital Archive. https:// digitalarchive.wilsoncenter.org/document/240253. Free translation from Chinese text by author.

45. 16 मई, 1959 को राजदूत पैन ज़िली ने माओ के निर्देश पर भारत के विदेश सचिव को कहा कि "कुल मिलाकर, भारत चीन का दोस्त है," और कि "चीनी लोगों के दुश्मन पूर्व में हैं –अमेरिकी साम्राज्यवादियों के कई सैन्य ठिकाने ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और फिलीपींस में हैं जो सभी चीन के खिलाफ हैं। चीन का मुख्य ध्यान और संघर्ष की नीति की दिशा पूर्व की तरफ, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की तरफ, शातिर और आक्रामक अमेरिकी साम्राज्यवाद की तरफ है, और ना कि भारत या दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण एशिया के किसी दूसरे देश की तरफ।" See Doc. 1409, Statement made by the Chinese Ambassador to the Foreign Secretary, in New Delhi, 16 May, 1959. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 3. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 2496-2500.

46. Doc. 1473, Telegram from Indembassy, Peking to Foreign, New Delhi, 09 September, 1959. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 3. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 2626-2633.

47. Jun, Niu. "1962: The Eve of the Left Turn in China's Foreign Policy." Working Paper. Cold War International History Project. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, October 2005. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/ NiuJunWP481.pdf.

48. Kalha, Ranjit Singh. *India-China Boundary Issues: Quest for Settlement.* (New Delhi: Pentagon Press, 2014). 102.
49. China. Embassy (India). "Cable from the Chinese Embassy in India, 'Overview of India's Foreign Relations in 1961.'" Report, January 1, 1962. PRC FMA 105-01519-01, 1-14. Translated by Anna Beth Keim. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/ document/116482.
50. Lui, Xuecheng. *The Sino-Indian Border Dispute and Sino-Indian Relations.* (Lanham, MD: University Press of America, 1994). 39.
51. Hu Zhefeng, *"Mao and the Sino-Indian Counter-attack in Self Defence"*, Bai Nian Chao No. 3/1999.
52. Doc. 1885, Letter from the Prime Minister of India, to Premier Chou En-lai, 27 October, 1962. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 4. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 3950-3951.
53. Jun, Niu. "1962: The Eve of the Left Turn in China's Foreign Policy." Working Paper. Cold War International History Project. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, October 2005. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/ NiuJunWP481.pdf.
54. Doc. 2021, Chou En-lai's interview with the correspondent of Associated Press of Pakistan, 31 March, 1963. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4301-4304.
55. Jun, Niu. "1962: The Eve of the Left Turn in China's Foreign Policy." Working Paper. Cold War International History Project. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, October 2005. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/ NiuJunWP481.pdf.
56. Ambassadors had been withdrawn in 1961.
57. Doc. 2267, Telegram from Indian Embassy, Peking to the Ministry of External Affairs, 01 May, 1970. India- China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4810.
58. Doc. 2269, Telegram from Indian Embassy, Peking to the Ministry of External Affairs, 06 May, 1970. India- China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4812.
59. Doc. 2275, Telegram from the Indian Embassy in Peking to the Ministry of External Affairs, 14 July, 1970. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4830.
60. Doc. 2276, Telegram from Peking to Ministry of External Affairs, 13 August, 1970. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4831.
61. गांधी ने टप्पिणी की कि "आप [चीन के साथ] सवाल का हल यह कहकर नही निकाल सकते कि मै यहां खड़ा हूं और मै यही रहूंगा। आपको पता लगाना होगा कि इसे कैसे सुलझाया जा सकता है।" See Doc. 2262, Prime Minister Indira Gandhi's replies to questions at a press conference, January 01, 1969. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018), p. 4798.
62. Jun, Niu. "1962: The Eve of the Left Turn in China's Foreign Policy." Working Paper. Cold War International History Project. Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, October 2005. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/ NiuJunWP481.pdf.
63. Lin, Biao, and Zedong Mao. "Mao Zedong's Talk at a Meeting of the Central Cultural Revolution Group (Excerpt)," March 15, 1969. Zhonghua renmin gongheguo shilu [A Factual History of the People's Republic of China] (Changchun: Jilin renmin chubanshe, 1994), vol. 3, Part 1, pp. 467-469. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111241.
64. Jiaxuan, Tang. *Heavy Storm and Gentle Breeze: A Memoir of China's Diplomacy*. First Edition. (New York: HarperCollins Publishers, 2011), p. 171.

65. Zhisui, Li Tai Hung-Chao. T*he Private Life of Chairman Mao: The Memoirs of Mao's Personal Physician Dr. Li Zhisui*. Translated by Tai Hung-Chao. (New York: Random House, 1994), p. 514.

66. आदेश में कहा गया : “अमेरिकी साम्राज्यवादी और सोवियत संशोधनवादी अपने गठजोड़ को मज़बूत कर रहे है और हमारी महान मातृभूमि पर अतिक्रमण करने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय प्रतिक्रियावादी भी घुसपैठ करने और हमारी राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने की बेकार कोशिश करने का मौका तलाश रहे हैं।” See China. Communist Party. Central Committee (CCP CC). “The CCP Central Committee's Order for General Mobilization in Border Provinces and Regions,” August 28, 1969. Obtained and translated by Michael Schoenhals. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/ document/110473.

67. Hua, Huang. “Meeting Four Indian Prime Ministers During One Offical Goodwill Visit.” In *Huang Hua Memoirs, First Edition*. 396-420. Beijing: Foreign Languages Press, 2008.

68. Doc. 2289, Statement by the Chinese representative Chiao Kuan-hua in the UN General Assembly, 07 December, 1971. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4852; Aijazuddin, F. S., ed. “Doc. 71.H.13, Memorandum of Conversation between General Haig and Ambassador Huang Hua, New York, 12 December 1971.” In *The White House and Pakistan: Secret Declassified Documents*, 1969-1974. 463-465. Karachi: Oxford University Press, 2002.

69. Aijazuddin, F. S., ed. “Doc. 73.13, Memorandum of Conversation between Mao Zedong and Kissinger, November 12, 1973.” In *The White House and Pakistan: Secret Declassified Documents*, 1969-1974. 617-619. Karachi: Oxford University Press, 2002.

70. Doc. 2313, Note by the Ministry of External Affairs on the recent India-China exchanges on The Border Issue. The Place of the border problem in the over-all India-China relations; Talks during Vajpayee's visits, 13 February, 1979. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4915.

71. Doc. 2314, Vice Premier Deng Xiaoping's interview with Krishna Kumar, Editor of the New Delhi based journal Vikrant, 21 June, 1980. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4920.

72. Xiaoping, Deng. “Promote the Friendship Between China and India and Increase South-South Cooperation.” The Selected Works of Deng Xiaoping, October 22, 1982. https://dengxiaopingworks.wordpress.com/2013/03/08/promote-the-friendship-between-china-and-india-and-increase-south-south-cooperation/.

73. Hua, Huang. “Meeting Four Indian Prime Ministers During One Official Goodwill Visit.” In *Huang Hua Memoirs, First Edition*. 396-420. Beijing: Foreign Languages Press, 2008.

74. नई स्थिति यह थी कि भारत को पहले पूर्वी सेक्टर में सार्थक रियायतें देनी होंगी, जिसके बाद चीन पश्चिमी सेक्टर में समान लेकिन अपरिभाषित रियायतें देगा।

75. Saran, Shyam. “Chapter 7: The India-China Border Dispute and After.” In *How India Sees The World: From Kautilya to the 21st Century*. 123-148. New Delhi: Juggernaut, 2017.

76. Deng, Xiaoping, and Valery Giscard d'Estaing. “Record of Conversation between French President Giscard d'Estaing and Vice Premier of the People's Republic Deng Xiaoping: First Meeting.” Memorandum of Conversation, May 13, 1975. Ministère des Affaires Etrangères, la Courneuve (MAE), Série Asie-Océanie, Sous-série Chine 1973-1980 (AO), 2174. Obtained and translated by Martin Albers. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/118648.

77. जनवरी 1979 में देंग ने राष्ट्रपति जिमी कार्टर से कहा कि “सोवियत संघ वियतनाम का इस्तेमाल चीन को परेशान करने के लिए करेगा।” See Nickles, David P., ed. “Document 205. Memorandum of Conversation.” In *Foreign Relations of the United States: 1977-1980*, Vol. 13. Foreign Relations of the United States.

78. (Washington: United States Government Printing Office, 2013), pp. 766-770. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v13.

79. Hua, Huang. “As Foreign Minister.” In *Huang Hua Memoirs, First Edition*. 287-294. Beijing: Foreign Languages Press, 2008.

80. Xiaoping, Deng. “Build Powerful, Modern and Regularized Revolutionary Armed Forces.” Deng Xiaoping, September 19, 1981. https://www.marxists.org/reference/archive/deng-xiaoping/1981/126.htm.

81. Doc. 2307, Interview given by Vice Premier Teng Hsiao-ping to Indian Journalists, 14 February, 1979. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4895.

82. “एशिया आधिपत्यवादियों द्वारा आक्रामकता और विस्तार का एक खतरनाक स्थान बन गया है।” See Doc. 2315, Commentary

by Xinhua Correspondent Zhou Cipu on Sino-Indian Relations, 24 June, 1980. India-China Relations 1947-2000 - A Documentary Study. Vol 5. 5 vols. Ed. A.S. Bhasin. (New Delhi: Geetika Publishers. 2018). 4922.

83. Hua, Huang. "As Foreign Minister." In *Huang Hua Memoirs, First Edition*. 287-294. Beijing: Foreign Languages Press, 2008.
84. Nickles, David P., ed. "Document 208. Memorandum of Conversation." In *Foreign Relations of the United States: 1977-1980*, Vol. 13. Foreign Relations of the United States. (Washington: United States Government Printing Office, 2013), pp. 772-782.
85. Xiaoping, Deng. "Our Principled Position On the Development of Sino-U.S. Relations." The Selected Works of Deng Xiaoping, January 4, 1981. https://dengxiaopingworks.wordpress.com/2013/02/25/ our-principled-position-on-the-development-of-sino-u-s-relations/.
86. ब्रेज़नेव ने कहा: "हमने कभी भी अपने देशों के बीच दुश्मनी और अलगाव की स्थिति को एक सामान्य घटना नहीं माना।" See Zubok, Vladislav. "The Soviet Union and China in the 1980s: Reconciliation and Divorce." Cold War History 17, no. 2 (April 3, 2017): 121–41. https://doi.org/10.1080/14682745.2017.1315923.
87. Hua, Huang. "As Foreign Minister." In *Huang Hua Memoirs, First Edition*. 287-294. Beijing: Foreign Languages Press, 2008.
88. Xiaoping, Deng. "We Must Safeguard World Peace and Ensure Domestic Development." The Selected Works of Deng Xiaoping, May 29, 1984. https://dengxiaopingworks.wordpress.com/2013/03/08/we-must-safeguard-world-peace-and-ensure-domestic-development/.
89. Xiaoping, Deng. "Speech At An Enlarged Meeting of the Military Commission of the Central Committee of the Communist Party of China." The Selected Works of Deng Xiaoping, June 4, 1985. https://dengxiaopingworks.wordpress.com/2013/03/18/speech-at-an-enlarged-meeting-of-the-military-commission- of-the-central-committee-of-the-communist-party-of-china/.
90. Deng, Xiaoping, and Masayoshi Ohira. "General Meeting of Prime Minister and Vice Premier Deng (Summary Record)," February 7, 1979. Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan, 01- 1237-1, 012-016. Contributed by Robert Hoppens and translated by Stephen Mercado. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/120021.
91. Nickles, David P., ed. "Document 204. Memorandum of Conversation." In *Foreign Relations of the United States: 1977-1980*, Vol. 13. Foreign Relations of the United States. (Washington: United States Government Printing Office, 2013). 755-766.
92. National Security Archive. "'Set the Nuclear Issue Aside'. Secretary of Defense Harold Brown to Ambassador-at-Large Gerard C. Smith, 31 January 1980, Enclosing Excerpts from Memoranda of Conversations with Geng Biao and Deng Xiaoping, 7 and 8 January 1980, Top Secret," January 31, 1980. https://nsarchive.gwu.edu/document/28189-document-3-set-nuclear-issue-aside-secretary-defense-harold-brown-ambassador-large.
93. Lui, Xuecheng. "Chapter 6: The Sino-Indian Détente." In *The Sino-Indian Border Dispute and Sino-Indian Relations*. Lanham, MD: University Press of America, 1994. 136-137.
94. Gokhale, Vijay. "The Road from Galwan: The Future of India-China Relations." Carnegie India, March 10, 2021. https://carnegieindia.org/2021/03/10/road-from-galwan-future-of-india-china-relations-pub-84019.
95. Xiaoping, Deng. "A New International Order Should Be Established With the Five Principles of Peaceful Coexistence As Norms." The Selected Works of Deng Xiaoping, December 21, 1988. https://dengxiaopingworks.wordpress.com/2013/03/18/a-new-international-order-should-be-established-with-the- five-principles-of-peaceful-coexistence-as-norms/.
96. Xiaoping, Deng. "We Are Confident That We Can Handle China's Affairs Well." The Selected Works of Deng Xiaoping, September 16, 1989. https://dengxiaopingworks.wordpress.com/2013/03/18/we-are-confident-that-we-can-handle-chinas-affairs-well/.
97. Zemin, Jiang. 1993. "Our Diplomatic Work Must Unswervingly Safeguard the Highest Interests of the State and the Nation." In *Selected Works of Jiang Zemin*. 1st Edition. Vol. 1. 3 vols. 302-308. Beijing: Foreign Languages Press, 2010.
98. Zemin, Jiang. 1989. "We Chinese Have Always Cherished Our National Integrity." In *Selected Works of Jiang Zemin*. 1st Edition. Vol. 1. 3 vols. 67-70. Beijing: Foreign Languages Press, 2010.
99. Zemin, Jiang. 1989. "Look to the Future in Developing Sino-US Relations." In *Selected Works of Jiang Zemin*. 1st Edition. Vol. 1. 3 vols. 81-82. Beijing: Foreign Languages Press, 2010.

100. "चीन और अमेरकि दोनों दुनिया में बड़े प्रभाव वाले देश हैं। नए वैश्विक माहौल के बीच, हमारे साझा हति घट नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं; और सहयोग की संभावना बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हम दोनों देशों के व्यापक, साझा हति हैं और हम मानव अस्तित्व और वकिास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साझा ज़िम्मेदारी लेते हैं।" See Zemin, Jiang. 1997. "Speech at the White House Welcoming Ceremony." In *Selected Works of Jiang Zemin*. 1st Edition. Vol. 2. 3 vols. 51-52. Beijing: Foreign Languages Press, 2012.

101. बीजिंग में 27 जून 1998 को राष्ट्रपतियों क्लिंटन और जियांग ज़ेमिन द्वारा जारी संयुक्त बयान में "शांतिपूर्ण और स्थिर दक्षिण एशिया में उनके साझा हितों" पर ज़ोर दिया गया, यह घोषणा करते हुए कि वहां शांति और स्थिरता की सुरक्षा करना उनकी साझा जिम्मेदारी है, और क्षेत्र में उनके बीच समन्वय "आवश्यक" है। See GovInfo. "1998 Public Papers 1077 - Joint Statement on South Asia." Government. Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, June 27, 1998. https://www.govinfo.gov/app/details/PPP-1998-book1/https%3A%2F%2Fwww.govinfo.gov%2Fapp%2Fdetails%2FPPP-1998-book1%2FPPP-1998-book1-doc-pg1077.

102. MEMRI. "Then Chinese Communist Party (CCP) Leader Jiang Zemin's 1993 Speech At Central Military Commission Outlines People's Liberation Army's (PLA) Military Strategy," May 20, 2022. https://www.memri.org/reports/then-chinese-communist-party-ccp-leader-jiang-zemins-1993-speech-central-military-commission.

103. Bush, George, and Ziyang Zhao. "Memorandum of Conversation between George H.W. Bush and Zhao Ziyang," February 26, 1989. Memcons and Telcons, George Bush Presidential Library and Museum. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/133956.

104. Dixit, Jyotindra Nath. *My South Block Years: Memoirs of a Foreign Secretary*. First Edition. New Delhi: UBS Publishers' Distributors Ltd., 1996. 235-237.

105. Saran, Shyam. "Chapter 7: The India-China Border Dispute and After." In *How India Sees The World: From Kautilya to the 21st Century*. 123-148. New Delhi: Juggernaut, 2017.

106. "U.S. Embassy China Cable 025699, 'ACDA Director Lehman's Beijing Consultations: Non-CWC Topics,' 19 August 1992, Secret, Excised Copy." State Department Freedom of Information Act Release, August 19, 1992. https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB114/chipak-23.pdf.

107. Heilmann, Katrin M, and Zukang Sha. "Oral History Interview with Sha Zukang." Interview, November 30, 2016. Contributed to NPIHP by Michal Onderco. History and Public Policy Program Digital Archive. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/177549.

108. Xiaoping, Deng. "First Priority Should Always Be Given To National Sovereignty and Security." The Selected Works of Deng Xiaoping, December 1, 1989. https://dengxiaopingworks.wordpress.com/2013/03/18/first-priority-should-always-be-given-to-national-sovereignty-and-security/.

109. Ruixiang, Zheng. "Shifting Obstacles in Sino-Indian Relations." *The Pacific Review* 6, no. 1 (January 1, 1993): 63–70. https://doi.org/10.1080/09512749308719022.

110. Gancheng, Zhao. "China-U.S.-India: Is a New Triangle Taking Shape?" *China Quarterly of International Strategic Studies* 02, no. 01 (January 2016): 1–16. https://doi.org/10.1142/S2377740016500019.

111. II Toast by H E President Jiang Zemin of the People's Republic of China at Welcoming Banquet Hosted by President Sharma of the Republic of India, 28 November 1996. (1997). *China Report*, 33(2), 236–237. https://doi.org/10.1177/000944559703300210.

112. Dixit, Jyotindra Nath. *My South Block Years: Memoirs of a Foreign Secretary*. First Edition. (New Delhi: UBS Publishers' Distributors Ltd., 1996), 24.

113. Gancheng, Zhao. "China-U.S.-India: Is a New Triangle Taking Shape?" *China Quarterly of International Strategic Studies* 02, no. 01 (January 2016): 1–16. https://doi.org/10.1142/S2377740016500019.

114. Ministry of External Affairs. "Joint Statement of the Republic of India and the People's Republic of China," April 11, 2005. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6577/ Joint_Statement_of_the_Republic_of_India_and_the_Peoples_Republic_of_China.

115. Saran, Shyam. "Chapter 7: The India-China Border Dispute and After." In *How India Sees The World: From Kautilya to the 21st Century*. 123-148. New Delhi: Juggernaut, 2017.

116. Zhaoxing, Li. "Chapter 7: 99.9% Versus 0.1%." In *Untold Stories of My Diplomatic Life*, First Edition. 140-152. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2019.

117. Qichen, Qian. *Ten Episodes in China's Diplomacy*. First Edition. New York: HarperCollins Publishers, 2005.

118. Zhaoxing, Li. *Untold Stories of My Diplomatic Life*. First Edition. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2019. p. 76.

119. Qichen, Qian. 2002. "The United States After September 11th." In *Ten Episodes in China's Diplomacy*. 315-323. New York: HarperCollins Publishers.

120. Jiaxuan, Tang. *Heavy Storm and Gentle Breeze: A Memoir of China's Diplomacy*. First Edition. (New York: HarperCollins Publishers, 2011), p. 199.

121. Zhang, Ketian. "Explaining Chinese Military Coercion in Sino-Indian Border Disputes." *Journal of Contemporary China*, (June 16, 2022): 1–18. https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2090081.

122. Bingguo, Dai. "Long Xiang Gongwu [The Dragon and Elephant Dancing Together]." In *Zhanlue Duihua: Dai Bingguo Huiyi Lu [Strategic Dialogue: Memoirs of Dai Bingguo]*, 267–96. Beijing: Renmin Chubanshe [People's Publishing House], 2016.

123. Cheng Ruisheng, "Enhancing Mutual Trust Between India and China," *China International Studies* 21, no.140 (2010): 140–50.

124. Bingguo, Dai. "Long Xiang Gongwu [The Dragon and Elephant Dancing Together]." In *Zhanlue Duihua: Dai Bingguo Huiyi Lu [Strategic Dialogue: Memoirs of Dai Bingguo]*, 267–96. Beijing: Renmin Chubanshe [People's Publishing House], 2016.

125. Ye Hailin, "The Influence of Identity Perception Bias on India-China Relations," China-India Dialogue, November 2020.

126. Li Jiacheng, "Developing China's Indian Ocean Strategy: Rationale & Prospects," *China Quarterly of International Strategic Studies* 3, no. 4 (2017): 481–97.

127. Ling Shengli, "Building a Community of Common Security: China's Approach to Its Neighborhood," *China International Studies* 68 (2018): 44–67.

128. Yang Xiaoping "Managing Leadership in Indo-Pacific: The US's Asia Strategy Revisited," *China Quarterly of International Strategic Studies* 3, no. 4 (2017): 463–80.

129. Yang Xiaoping "Managing Leadership in Indo-Pacific: The US's Asia Strategy Revisited," *China Quarterly of International Strategic Studies* 3, no. 4 (2017): 463–80.

130. Gancheng, Zhao. "China-U.S.-India: Is a New Triangle Taking Shape?" *China Quarterly of International Strategic Studies* 02, no. 01 (January 2016): 1–16. https://doi.org/10.1142/S2377740016500019.

131. Shi Hongyuan, "The Indian Ocean Policy of the Modi Government," *China International Studies* 69 (2018): 86.

132. Jinping, Xi. 2013. "Build a New Model of Major-country Relationship Between China and the United States." In *The Governance of China*. Vol 1. 4 vols. 304. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd.

133. Jinping, Xi. 2013. "Build a New Model of Major-country Relationship Between China and the United States." In *The Governance of China*. Vol 1. 4 vols. 304-306. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd.

134. Yi, Wang. "पारस्परिक फायदों वाले सहयोग के एक नए प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए जाएं – इस सवाल का चीन द्वारा दिया गया जवाब कि '21वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय संबंध किस दिशा में जा रहे हैं' By Wang Yi Minister of Foreign Affairs People's Republic of China." Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, July 1, 2016. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/201607/ t20160701_468628.html.

135. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. "Interview with China Correspondent of *The Hindu* by Foreign Minister Wang Yi," June 8, 2014. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/ zyjh_665391/201406/t20140608_678171.html.

136. Foreign Minister Wang Yi Meets the Press," March 8, 2015. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/201503/t20150308_468552.html.

137. Conversation between senior Chinese official and the author in April 2017.

138. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. "Wang Yi: China and India Should Make Correct Choice in Direction of Bilateral Relations," December 12, 2017. https://www.fmprc.gov.cn/ mfa_eng/gjhdq_665435/2675_665437/2711_663426/2713_663430/201712/t20171213_513105.html.

139. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. "Wang Yi Meets with Foreign Secretary Vijay Gokhale of India," February 23, 2018. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2675_665437/2 711_663426/2713_663430/201802/t20180226_513115.html.

140. World Economic Forum. "President Xi Jinping's Message to The Davos Agenda in Full," January 2022. https://www.weforum.org/agenda/2022/01/address-chinese-president-xi-jinping-2022-world-economic-forum-virtual-session/.

141. World Economic Forum. "President Xi Jinping's Message to The Davos Agenda in Full," January 2022. https://www.weforum.org/agenda/2022/01/address-chinese-president-xi-jinping-2022-world-economic-forum-virtual-session/.

142. Xu Jian, "China's Major Country Diplomacy and Sino-Indian Relations," *China International Studies* 70, no. 37 (2018): 41–42.

143. Patranobis, Sutirtho. "'Hope India Continues to Follow an Independent Foreign Policy': China." *Hindustan Times*. July 22, 2020, sec. India News. https://www.hindustantimes.com/india-news/hope-india-continues- to-follow-an-independent-foreign-policy-china/story-URH1Hs7fnfQ8aqWp8vvjGJ.html.

144. Zhang Jiadong, "Are US and India Already in Quasi-Military Alliance?," *Huanqiu Shibao*, October 30, 2020.

145. Rong Ying, "The Modi Doctrine & the Future of India-China Relations," *China International Studies*, no. 26 (2018): 26–43.

146. Ye Hailin, "The Influence of Identity Perception Bias on India-China Relations," China-India Dialogue, November 2020.

147. Zhang, Ketian. "Explaining Chinese Military Coercion in Sino-Indian Border Disputes." *Journal of Contemporary China*, (June 16, 2022): 1–18. https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2090081.

148. Pu, Xiaoyu. "The Status Dilemma in World Politics: An Anatomy of the China–India Asymmetrical Rivalry." The Chinese Journal of International Politics 15, no. 3 (September 1, 2022): 227–45. https://doi.org/10.1093/cjip/poac015.

149. Zhang, Ketian. "Explaining Chinese Military Coercion in Sino-Indian Border Disputes." *Journal of Contemporary China*, (June 16, 2022): 1–18. https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2090081.

150. Krishnan, Ananth. "China Defends Move to Block Listing of Lashkar Terrorist." *The Hindu*. September 19, 2022, sec. World. https://www.thehindu.com/news/international/china-defends-move-to-block-listing-of- lashkar-terrorist/article65909715.ece.

151. Zhang, Ketian. "Explaining Chinese Military Coercion in Sino-Indian Border Disputes." *Journal of Contemporary China*, (June 16, 2022): 1–18. https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2090081.

152. Srinivasan, Meera, and Ananth Krishnan. "Chinese Vessel Yuan Wang 5 Reaches Sri Lanka's Hambantota Port." *The Hindu*. August 16, 2022, sec. World. https://www.thehindu.com/news/international/chinese- vessel-reaches-sri-lankas-hambantota-port/article65774283.ece.

153. The Times of India. "'Quad' Move Will Dissipate like Sea Foam: China," March 8, 2018. https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/quad-move-will-dissipate-like-sea-foam-china/ articleshow/63221055.cms.

154. Hailin, Ye. "The Influence of Identity Politics on the Prospects of Sino-Indian Relations." *Indian Ocean Economic and Political Review*, no. 3 (2020): 1–12.

155. Yi, Wang. "Speech by Foreign Minister Wang Yi at the Opening of Symposium on International Developments and China's Diplomacy in 2017." Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, December 10, 2017. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/201712/t20171210_678651.html.

156. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. "Wang Yi: China and India Should Stick to Long-Term Perspective, Win-Win Mentality and Cooperative Posture," March 25, 2022. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202203/t20220326_10656095.html.

Unit C-5 & 6 | Edenpark | Shaheed Jeet Singh Marg | New Delhi, India 110016 | P: +011 4008687

CarnegieIndia.org